खण्ड-07 सत्र-05 अंक-62

शुक्रवार 01 मार्च, 2024
11 फाल्गुन, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 शुक्रवार, 1 मार्च, 2024/11 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-62

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	3-41
3.	दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24	42-58
4.	समिति का प्रतिवेदन	59
5.	अल्कालिक चर्चा (नियम-55)	60-102

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 — शुक्रवार, 1 मार्च, 2024/11 फाल्गुन, 1945 (शक) — अंक-62

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
2. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
3. श्री अजय दत्त
4. श्री अब्दुल रहमान
5. श्री बी. एस. जून
6. श्री दिनेश मोहनिया
7. श्री गिरीश सोनी
8. श्री हाजी युनूस
9. श्री जय भगवान
10. श्री जरनैल सिंह
11. श्री महेंद्र गोयल
12. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
13. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री एस. के. बग्गा
16. श्री विशेष रवि
17. श्री मदन लाल
18. श्री नरेश यादव
19. श्री पवन शर्मा
20. श्री प्रलाद सिंह साहनी

21. श्री प्रवीण कुमार
22. श्री ऋतुराज गोविंद
23. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
24. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
25. श्री रोहित कुमार
26. श्री संजीव झा
27. श्री सोमदत्त
28. श्री शिव चरण गोयल
29. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 शुक्रवार, 1 मार्च, 2024/11 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-62

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, 280। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं माननीय विधायकों से, कल भी मैंने कहा था 280 में जो आपने लिखकर दिया है, वही कृपा बोलें, अगर उससे अधिक कुछ बोलेंगे तो वो रिकोर्ड में नहीं आएगा, धन्यवाद। श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः स्पीकर साहब सिर्फ ये दो लाइन ही बोलनी है, इस मसलें में तो बोलूंगा ना।

माननीय अध्यक्षः नहीं तो आगे से पूरा लिखकर दीजिए ना, उसपर एक्शन कैसे होगा।

श्री जरनैल सिंहः अच्छा।

माननीय अध्यक्षः उसपर हम समझेंगे क्या, देखेंगे क्या।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री जरनैल सिंहः थैंक्यू स्पीकर साहब। सर ये जो समस्या मैं बताने जा रहा हूं, ये मेरे को लगता है मेरे क्षेत्र के साथ-साथ बहुत सारे दिल्ली वाले रोज इस समस्या से झूझते हैं। इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो आपने पीछे प्रथा चलाई थी 280 में हम सवाल उठा देते हैं, तो पीछे क्या होता था साथ के साथ डिपार्टमेंट से कोई ना कोई फोलोअप हो जाता था। अब पिछले फिर कुछ समय से डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आता समस्या उठाने के बाद और कोई रिस्पोंस नहीं आता। समस्या ये है सर बिजली विभाग द्वारा अलग-अलग सड़कों में, पार्कों में, गलियों में खम्बे और ट्रांस्फार्मर लगाए गए हैं। अब इनकी वजह से कई जगह इतना ज्यादा ट्रैफिक ऑब्सट्रक्शन होता है कि वहां से निकलना मुश्किल हुआ पड़ा है, हटाते वो है नहीं बिजली वाले। कई बारी उनसे लैटर लिख दिये, कई बारी पत्राचार हो गया। समझ आती है दिल्ली में स्पेस लिमिटेड है, पर जहां बहुत गम्भीर समस्या बन गई है जैसे मेरे एरिया में कुछ सड़कों के लगभग बीचों-बीच में खम्बा लगा हुआ है और पूरा दिन वो सड़क सिर्फ इस वजह से जाम रहती है कि वो बिजली का खम्बा वहां लगा हुआ है, कई जगह ट्रांस्फार्मर लगे हुए हैं। कई जगह ऐसी रिस्की जगह पर लगे हुए हैं जहां आसपास से लोग गुजर रहे हैं, साथ में नाला बह रहा है, ट्रांस्फार्मर लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो इनकी कोई

रिसर्च करवाई जाए, पूरी दिल्ली में कितने ऐसे खम्बे हैं जिनकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। फिर इनको अल्टरनेट स्पेस देकर इनको shifting का प्रोविजन कराया जाए, जो बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनिज हैं वो कुछ खास इसपर ध्यान दे नहीं रही। हमारे बार-बार कहने के बाद भी ध्यान नहीं दे रही। अगर बहुत ज्यादा कहो तो कहते हैं आप खर्चा दे दो एमएलए लैड फँड से इसको हम शिफ्ट करा देते हैं, जबकि ये तो बिजली कम्पनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से यही कहना है कि इस समस्या पर गौर किया जाए और उसका समाधान कराया जाए, बहुत सारे दिल्लीवासी हर दिन इस समस्या से झूझ रहे हैं, थैंक्यू स्पीकर साहब।

माननीय अध्यक्षः श्री रोहित कुमार जी।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी जो आपने मुझे अपने क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के बारे में इस सदन के पटल पर अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः रोहित जी एक सैकंड अभी आपका नम्बर नहीं है प्लीज। मैं गलत बोल गया हूं, थोड़ी देर में आएगा। श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों। नहीं नम्बर से आने दीजिए, मेरे से गलत अनाउंस हो गया, श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों। बैठिए प्लीज।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरी एक मायापुरी जेजे कलस्टर, जिस कलस्टर में तकरीबन 15 से 20 हजार लोग झुग्गीवासी निवास करते हैं और वहां पर एक दो साल से बहुत ही समस्या चल रही है। कम से कम 40 साल पुराना, वहां पर अध्यक्ष जी एक फ्रिेब जेएससी बना हुआ है, प्रीफैब जेएससी में जितने भी उसके दरवाजे हैं या प्रिफैब जेएससी में उसकी छतें जो टीन की छतें होती हैं, उसको बार-बार हम लोग रैनोवेट उसको करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो समय है, उसकी मियाद है, क्योंकि वो 40 साल पुराना हो चुका है प्रिफैब जेएससी, तो उसको पक्का जेएससी हमें बनवाना है और मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि मेरी आपने एक सीईओ के साथ मीटिंग करवाई थी, डूसिब के जो हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं। उसके बाद पूरे जेजे कलस्टर में शायद मैंने कभी इतिहास में मैंने नहीं सुना था कि झुग्गियों में भी एक सुंदर-सुंदर टाइल्स लगवाकर, उन गरीब लोगों की गलियों को सुंदर बनवाया है, नालियाँ बनवाई हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो मेरी एक मूलभूत समस्या है, प्रिफैब जेएससी की इसमें की एक ऐसी आशंका बना रहती है कि महिलाओं के साथ कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उसको जेएससी पक्का बनवाना है हमें। अध्यक्ष जी मेरा इसी के साथ एक मेरा इस प्रश्न में मेरा लिखा हुआ है, एक प्रयोग विहार जेजे कलस्टर है उसमें तकरीबन 40 साल पुराना स्लम विभाग ने एक बस्ती विकास केंद्र बनवाया था जो कि

150 मीटर का बना हुआ है, उसका बिल्कुल लैंटर गिर गया है, खत्म हो चुका है, उसमें लोग अपना छोटे-छोटे अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों के जन्मदिन वगैरा मनवाते हैं। तो एक मेरी ये भी फाइल थी, लेकिन हमेशा डूसिब विभाग का ये कहना है कि हमारे यहां चीफ इंजिनियर नहीं है, जबकि अभी 5 महीने से चीफ इंजिनियर की भी पोस्टिंग हो चुकी है और कहीं न कहीं आप, मैं तो ये कहूंगी अध्यक्ष जी, मेरी ये समस्या बहुत गम्भीर समस्या है और बहुत जल्दी करवाएंगे तो झुग्गीवासी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद जय हिंद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान अखिलेश त्रिपाठी जी, अनुपस्थित। प्रलाद सिंह साहनी जी।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आपने इस मैटर पर मेरे को बोलने का मौका दिया। मेरे पूरे क्षेत्र में जामा मस्जिद, नवाब गंज, तिलक बाजार, सिविल लाइन तमाम जगहों पर सीवर लाइनों के संबंधित सरायफूस तीस हजारी में पानी के संबंधित बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसी तरह ईएनएम विभाग जो है जो मोटरें चलाता है, वो ट्यूवेल की जो मोटरें हैं सीवर के अंदर वो नहीं चला पाते, पीने का पानी जो है, वो ऊपर मंजिलों पर जाता है, reservoir बने हुए हैं मगर उनकी मोटर जो हैं, वो नहीं चलती जिस वजह से जामा मस्जिद के तमाम एरिये में जहां reservoir बना हुआ है, जहां सरायफूस में रिजरवायर बना हुआ है,

वहां दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज ये है, जनता काफी बढ़ गई है और इलाके के अंदर जो reservoir बने हुए हैं वो जर्जर हालत में हैं तथा उनकी हालत भी खराब है और छोटे भी है। मेरी आपके मार्फत से मेरी विनती है कि आप उनको आदेश दें कि उनके टैंकर बड़े कर दें ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः नरेश यादव जी (अनुपस्थित)। श्रीमान शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मैं अपनी मोती नगर विधानसभा की गम्भीर समस्या की तरफ ध्यान दिलवाना चाहता हूं आपका। हमारे यहां पर एक सतगुरू राम सिंह मार्ग जो रामा रोड इंडस्ट्रीयल एरिया है वहां पर और इसके ऊपर कम से कम भी 10 हजार उद्योग हैं और यहां पर लाखों लेबर काम करती है और वहीं पर एक है बी-58 जिसमें लगभग 15 हजार लेबर रहती है। हमारे यहां पर एक ड्रेन बनी हुई है जो कि 24 घंटे मैक्सिमम ओवरुलो करती है और ये पिछले कई सालों से लगातार बह रही है। जब इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया गया तो ये पता लगा कि 2011 में रंजीत नगर, प्रेम नगर से जो ड्रेन आती थी रेलवे लाइन के नीचे से वो लाइन कहीं ना कहीं बंद कर दी गई जो पहले वहां पर बना अभी 11-12 में मैट्रो स्टेशन बना है, वो मैट्रो स्टेशन बनने से उस नाले को बंद कर दिया गया और उस बंद करने से वो जो अब नाला

जोड़ दिया गया पीडब्ल्यूडी की ड्रेन के अंदर और जलबोर्ड के सीवर के अंदर। लेकिन उसका जो पानी की खपत है वो ज्यादा है और वो ड्रेन जो है छोटी है जिसकी वजह से वो पानी निरंतर सड़कों पर बहता है, विकराल स्थिति बनी हुई है। कई बारी अधिकारियों को कह चुके हैं कि इसको रिमॉडलिंग कर दें जिससे वो पानी की जो पूरी खपत वहां से आती है प्रेम नगर से, बलजीत नगर से उसकी क्षमता बनेगी पूरी तभी वो काम चलेगा। कई बारी पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर जल बोर्ड के सीवर को बार–बार इंटीमेट करने के बाद मीटिंग करने के बाद अभी 25 दिन पहले हमारे तमाम जो बड़े सीनियर ऑफिसर भी वहां पर विजिट पर आए थे, उनके बावजूद भी वहां पर उस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी ये बहुत गम्भीर समस्या है, इसको अपने संज्ञान में लेते हुए इसपर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएं जिससे वहां पर आने–जाने वाले लाखों लोगों को राहत मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद, शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: श्री बी एस जून साहब।

श्री बी एस जून: धन्यवाद स्पीकर सर। सर ज्यूं–ज्यू समर सीजन approach करता है दिल्ली में फायर के incident बढ़ती चली जाती है। पीछे अलीपुर में आग लगी 11 लोग जलकर मर गए, काफी प्रोपर्टी का नुकसान हुआ। उसके बाद सैक्टर–10 में आग लगी, एक लेडी की डैथ हो गई, कुछ इंजर्ड हुए प्रोपर्टी का भी नुकसान हुआ। उससे पहले मेरा एक वार्ड है राजनगर उसमें आग

लगी 8 फलैट कम्पलिटली जल गए। सर दिल्ली पुलिस का एक विंग है पीसीआर उसका एक रिस्पोंस टाइम है कि इंसीडेंट के 6 मिनट के अंदर-अंदर हम प्लेस ऑफ इंसीडेंट पर पहुंचेंगे, rescue के लिए। अब मुझे नहीं मालूम सर फायर ब्रिगेड में ऐसा कोई रिस्पोंस टाइम फिक्स किया गया है या नहीं किया गया है। सर हमने देखा कि पीसीआर वैन जगह-जगह स्टेशंड है। इसी aspect पर काम करते हुए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्रा ने एक स्कीम लेकर आए कि हम मोबाइल फायर वैन्स जगह-जगह स्टेशन करेंगे। कंजेस्टीड एरिया हो, कंजेस्टीड मार्केट हो, इंडस्ट्रीयल एरिया हो या ऐसी जगह जहां फायर बड़े टैंडर ना पहुंच सके। अगर स्मॉँल यूनिट, मोबाइल यूनिट्स सर ऐसी जगह पर place की जाएं तो मैं समझता हूं कि फायर के incident से इनसे कम से कम नुकसान होगा। क्योंकि फायर की गाड़ी आलमॉस्ट तब पहुंचती है जब डैमेज हो चुका होता है, लाइफ का भी और प्रोपर्टी का। ये एक अच्छा कनसैप्ट है, हमने पीछे अखबार में पढ़ा था कि शायद दिल्ली में भी इसको स्टार्ट करने की योजना है, अगर है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं है तो इसपर गौर किया जाए सर। इससे particularly समर सीजन में बहुत ही बेनिफिसियल ये चीज रहेगी ताकि हम मोबाइल फायर टेंडर्स या यूनिट जो है जगह-जगह important स्ट्रैटजिक चवपदजे पर उनको स्टेशन करें। बोलने का समय दिया सर बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान बिधूडी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 280 के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में और उसके बाद भी दिल्ली के लोगों से ये वायदा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में 25 नए कॉलेज खोलेगी। हर साल 5 कॉलेज खोले जाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले 9 सालों में सरकार एक भी कॉलेज खोल नहीं पाई। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बड़ी आबादी जिसकी संख्या कम से कम 2 करोड़ हो गई जो दिल्ली के गांवों में एक्सटैंडिड आबादी में, अनोथराइज्ड कॉलोनिज में, पुनर्वास कॉलोनियों में, झुग्गी-झोपड़ियों में और जहां जनता सिंजे हैं उसमें रहती है और इन क्षेत्रों में हमारे छात्राओं को बहुत कठिनाई होती है, उनको शहर की तरफ वो आ नहीं सकते, जल्दी से उनको कॉलेज में उनका दाखिला मिलता नहीं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक दिल्ली में 25 कॉलेज खोलें और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जो गांव है, ग्रामसभा की सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उस जमीन को, उसकी पहचान करके, जहां-जहां ग्रामसभा की जमीन है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल दिल्ली की सरकार का है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। तो उन जमीनों के ऊपर जो सरकार की कमिटमेंट है, कम से कम इन क्षेत्रों

में कॉलेज खोलने की शुरूआत होनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अभी जो गांव है जिनके पास ग्राम सभा की जमीन है और गांवों की जमीन के ऊपर ही अनोथराइज्ड कॉलोनिज बनी हुई हैं, गांवों की जमीन के ऊपर ही झूग्गी-झोपड़ी है, गांवों की जमीन के ऊपर ही पुनर्वास बस्ती है और गांवों की जो एक्सटैंडिड आबादी है इसमें एक बड़ी संख्या गरीब लोगों की है। तो छात्राओं की ये डिमांड रहती है, मांग रहती है कि उनके क्षेत्रों में यदि सरकार कॉलेज खोल देती है तो उनको बहुत लाभ हो जाएगा। मैं अंत में एक बार फिर आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने वायदे के मुताबिक 25 कॉलेज खोलने के लिए कदम उठाएं और दिल्ली देहात में जहां-जहां ग्राम सभा की जमीन है, जहां ये दो करोड़ आबादी रहती है वहां से उसकी शुरूआत करें। तो मैं यही आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार से और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से आग्रह करना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी यहां मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं थोड़ा। ओमप्रकाश शर्मा जी जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी constituency में आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली सरकार ने खोली है। दूसरा मेरी विधानसभा में डीटीयू जो विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है उसका कॉलेज कमर्शियल विंग खोला 6 साल हो गए। मैं दोनों अगल-बगल की तीन कॉलेजों का जिक्र आपसे कर रहा हूं, अपनी

विधानसभा का ओम प्रकाश जी बाकी विधान सभा का मैं जिक्र नहीं कर रहा।

...व्यवधान..

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड मैं जवाब दे दूं।

माननीय नेता, प्रतिपक्षः वो पुराने हैं?

माननीय अध्यक्षः पुराने नहीं है डीटीयू। आप बिधूड़ी जी गलत स्टेटमेंट मुझे, आईपी यूनिवर्सिटी मैं अगर इसपर पूरा लैक्चर देने लग गया 10 मिनट लग जाएंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है, आपकी जानकारी में है सारा का सारा विषय।

माननीयनेता प्रतिपक्षः लेकिन मेरी जो भावना है वो यही है।

माननीय अध्यक्षः नहीं,ये कहना गलत है किएक भी कॉलेज नहीं खोला। डीटीयू का कॉमर्शियल विंग मेरी यूनिवर्सिटी में हमारा सुखदेव कॉलेज चलता था, वो रोहिणी शिफ्ट हुआ और उसकी जगह डीटीयू का कमर्शियल विंग पहली बार वहां खोला गया। तीसरी डाइट का कॉलेज मेरी विधानसभा में खोला गया, ये तीन कॉलेजों का मैं विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूं, धन्यवाद। श्री सोमदत्त जी।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष जी एक सैकंड।

माननीय अध्यक्षः हाँ।

माननीय परिवहन मंत्री: जो बिधूड़ी जी बार-बार ये allegation लगा रहे हैं, तो मेरी विधानसभा में रोशनपुरा गांव की लगभग 25 से 30 एकड़ जमीन दिल्ली यूनिवर्सिटी को अलॉट की गई 1987 में, 1987 से लेकर आज तक तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम चिट्ठियाँ लिखने के बावजूद, मीटिंगस करने के बावजूद, वहां तक आज तक एक भी ईंट नहीं लगी है। तो ये जो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आप ये रवैया देख लीजिए। जबकि पूरे जितनी भी rural बैल्ट है वहां के बच्चें काफी किलोमीटर चल कर, कम से कम 40 से 50 किलोमीटर चल कर दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं। तो बिधूड़ी जी आपको ये भी देखना चाहिए और आपको केंद्र सरकार को भी बोलना चाहिए कि जमीन दी थी ग्रामसभा की जमीन थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को दी इस उम्मीद में की वहां कॉलेज बने, वहां यूनिवर्सिटी बने और वहां के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि उनको पूरा-पूरा दिन जो है बसों में धक्के ना खाना पड़े। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा विचार कीजिए और उनको बोलिए की वहां तुरंत कॉलेज वगैरा बनाने की कार्रवाई चालू करे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं आपका उसमें आएगा 280 में उसमें बोल दीजिएगा। श्री सोमदत्त जी। आधा घंटा वैसे ही लेट हाउस शुरू

होता है, आप लोग आते नहीं हैं समय पर, बड़ी दिक्कत होती है मुझे।

श्री सोमदत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा सदर बाजार बड़ी सघन आबादी वाला क्षेत्र है और इसके अंदर बहुत छोटी-छोटी गलियाँ बनी हुई हैं, जहां अक्सर अंधेरा, डार्क स्पोट्र्स की बहुत समस्या रहती थी और टाटा पावर टीपीडीडीएल, बीएसईएस और एमसीडी जो भी स्ट्रीट लाइटें लगाती है वो केवल इलैक्ट्रीक पोल के ऊपर लगाती है, यहां मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा, बड़ी संख्या में उनके द्वारा मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत लाइटें प्रोवाइड कराई गई, वो लाइटें उन डार्क spots को उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया, उन छोटी-छोटी गलियों के अंदर भी लगी और बड़ी संख्या में बुजुर्ग माताएं, बहनें अपना आशीर्वाद देती हैं इनके लिए। लेकिन साथ ही साथ अब उनमें से काफी लाइटें खराब होने लगी हैं, मेंटेनेंस का इशू आने लगा है। मेरा आपसे रिक्वैस्ट है उन स्ट्रीट लाइटों को जो मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए व्यवस्था बनाई जाए क्योंकि कोई भी एजेंसी उनको मेंटेन नहीं कर रही है, उन खराब लाइटों को ठीक नहीं कर रही और साथ ही साथ पूरी दिल्ली की सभी विधानसभाओं में मेरी विधानसभा में स्ट्रीट लाइटें एडिशनल रिक्वायर्मेंट है, इसी योजना के तहत मेरी आपसे प्रार्थना है, अडिशनल लाइटें और उपलब्ध कराई जाएं। धन्यवाद, जयहिंद, जयभारत।

माननीय अध्यक्ष: जयभगवान जी।

श्री जयभगवान: माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं आपका ध्यान बवाना विधानसभा के सैक्टर-20 और सैक्टर-24 की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां पर दो शराब की दुकानें हैं जो कि मैन रोड पर हैं और जिसकी वजह से, क्योंकि वो रेजिडेंशनल एरिया के अंदर है और काफी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती, क्योंकि जो लोग वहां पर शराब खरीदते हैं वो वहीं पर साथ में गाड़ियाँ लगाकर, पार्क के साथ में बैठकर के वहां पर दारू पीते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बार-बार जो आरडब्ल्यूए है उन्होंने दिल्ली पुलिस को बार-बार बोला, लेकिन पुलिस वहां पर कुछ नहीं करती अध्यक्ष महोदय। पुलिस का एक स्लोगन है शांति-सेवा-न्याय, बात करती है लेकिन लोगों को शांति-सेवा और जो न्याय है वो नहीं मिल पा रहा। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस वहां पर प्रशासन को टाइट करे जिससे की जो आम लोग हैं, जो आसपास की आरडब्ल्यूए है, चाहे वो पॉकेट-7 है, चाहे वो पॉकेट-8 है, चाहे वो पॉकेट-9 है, सैक्टर-24 और सैक्टर-20 के अंदर पॉकेट-16 और पॉकेट-13, यहां के जो residents है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि शराब की दुकान की वजह से लगातार जाम लगा रहता है और बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और आसपास जो है वो अलग-अलग तरह की एक्टीविटिज करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसपर अंकुश लगाया जाए, दिल्ली पुलिस इस पर ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा अभी-अभी

माननीय बिधूड़ी बोल रहे थे, तो उसपर एक ही मिनट मैं लूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली के अंदर।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए।

श्री जयभगवानः सर एक ही मिनट में बोल दूंगा सर, एक ही मिनट में खत्म कर दूंगा सर। दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटियाँ बनें। लेकिन डीडीए ने सर रोक लगा रखी थी। अभी मेरे इलाके के अंदर सरकार ने 32 करोड़ की लागत से मैडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जगह ली है, लेकिन उसकी जो फाइल है 2015 में हमने पैसा जमा कराया और बीच में 3 साल फाइल ही खो दी डीडीए ने। डीडीए से हमने फाइल निकलवाकर अभी जमीन ली है, हैंडओवर की है और अब उसके अंदर मैडिकल यूनिवर्सिटी सरकार बनाएगी। दूसरी अदिति कॉलेज के लिए भी हमने जगह मांगी डीडीए से काफी दिनों से मांग रहे हैं, लेकिन डीडीए उसको हैंडओवर नहीं कर रही है। तीसरी बात सर अभी क्योंकि जगह ना होने की वजह से मेरे यहां DTU college के अंदर सरकार ने गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल बनाये हैं क्योंकि जगह डीडीए द्वारा नहीं दी जा रही है अगर डीडीए देगी तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार लगातार यूनिवर्सिटियां खोलेगी और एक चीज़ और सर मैं कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं अब हो गया।

श्री जय भगवानः नहीं सर बस एक ही एक मिनट, सर आधे मिनट में कर रहा हूं मैं। अभी माननीय बिधूड़ी जी बोल रहे थे कि जो ग्राम सभा की जो ज़मीन है वो काफी मात्रा में सभी गांव के अंदर पड़ी हुई है लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि ये जो केन्द्र सरकार ने सारी जो ग्राम सभा की ज़मीन है चाहे वो शमशान घाट की चाहे वो बारात घर की है चाहे वो पार्कों की ज़मीन है सारी अर्बनाइज़ करने के बाद सारी हैंडओवर कर ली है और डीडीए इसको बनाने के लिये एनओसी नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे मौका दिया धन्यवाद, नमस्कार।

माननीय अध्यक्षः श्री अखिलेश त्रिपाठी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई ये बहस का नहीं आपने बात रखी उन्होंने बोल दिया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अभी सारे गांव अर्बानाइज़ नहीं हुये हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिये कोई नहीं अखिलेश त्रिपाठी जी।

....व्यवधान....

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 280 में अति महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्षः जो लिखकर दिया है वो ही बोलियेगा।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्ष महोदय, मैं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले डूसिब के शौचालयों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरी दिल्ली में जो जन-सुविधा केन्द्र बने हुये हैं। मेरे पास कल वहां के सारे कर्मचारी मेरे विधानसभा के उठकर आये और उन्होंने बताया कि तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच, छः-छः महीने से उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और जब उसके पीछे अधिकारियों से पता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि जो काम करने के लिये जिसको टेंडर दिया गया है, उसका पेमेंट छः-छः महीने से नहीं हो पाया है इसलिये अब वो सैलरी भी नहीं दे रहा है। यही नहीं वो काम करने वाली एजेंसी जो कर्मचारी हैं उनको श्रम विभाग का जो कानून है कि minimum wage कम से कम उनको मिलना चाहिये कर्मचारियों को वो minimum wage भी नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है जहां पर दिल्ली में आज़ादी के बाद कुल मिलाकर के हर सरकारों ने मिलकर के 15 हज़ार टॉयलेट के यूनिट बनाये थे हमारी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तकरीबन 20 हज़ार यूनिट शौचालय बनाने का काम किया, लोगों को सुविधा देने का काम किया पहले शौचालय पैसे देकर के लोग यूज़् करते थे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जन-सुविधा केन्द्रों को निशुल्क करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी एल.जी. के माध्यम से उसको भी बंद करने की

कोशिश कर रही है, ये भी इनकी आंखों में चुभ रहा है। कितना दिल्ली के लोगों को मारेंगे, मुझे नहीं पता चल रहा है, आप पेंशन लोगों का बंद करेंगे, लोगों को नौकरी से निकालेंगे।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी जो इसमें लिखा है उसको पढ़िये।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि उन कर्मचारियों को होली मनाने के लिये अवसर मिले, उनको तनख्वाह मिल जाये समय पर और जो भी बताया गया है कि फाइनांस सेक्रेटरी ने इस पूरे बजट को रोक रखा है और शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले डूसिब को वो पैसा नहीं मिल पाया। इस नाते पेमेंट नहीं हो पा रहा है वो पेमेंट हो, कर्मचारियों का हित हो और सबको minimum wages मिले यही मैं आपसे आग्रह करने के लिये यहां पर खड़ा हुआ था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी, श्री रोहित कुमार, राजेश जी आ गये हैं चलिये, बोलिये-बोलिये-बोलिये।

श्री राजेश गुप्ताः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में सवाल लगाने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित, मेरे सावन पार्क, अशोक विहार मेरे एरिया में एक जगह आती है जिसके अंदर एक जंपस मदक बनता है, उसके पीछे की अगर रेलवे की लाइन आ जाती है

और उसके बाद में माननीय अखिलेश पति त्रिपाठी जी की विधानसभा आ जाती है, वो पीछे से पानी की पाइन लाइन तो ला नहीं सकता। वहां हमने दो ट्यूवेल लगवाये और बहुत मुश्किल से लगवाये लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी का हमारे मंत्री जी का और VC sahab का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस पर काम हो पाया। उससे कुछ तो हल हो गया लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि पानी की पाइप लाइन हम वहां पर ले जाना चाहते हैं और बीच में एक डीडीए का पार्क है जो काफी बड़ा पार्क है जो पीडब्ल्यूडी का part है वहां पर तो हमने लाइन डाल ली लेकिन डीडीए उस लाइन को हमें डाल नहीं दे रहा जिस वजह से सावन पार्क में वो पानी पीछे पहुंच नहीं पा रहा। नार्मल डेज़ में तो फिर भी पानी की सप्लाई हो जाती है लेकिन जब कभी भी ये जो बार-बार अमोनिया बढ़ जाता है जो आप देखते हैं जो पानीपत से पता नहीं छोड़ दिया जाता है कि अपने आप आ जाता है भगवान ही जानता है लेकिन ये साल में दो-तीन बार ऐसी समस्यायें होती हैं और या कभी-कभी गर्मी के दिनों में बहुत समस्या होती है। तो सावन पार्क के उस एरिया में खासकर के आखिरी का जो जंपस मदक बनता है तो उसमें पानी नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपके माध्यम से ये जल बोर्ड तक बात पहुंचाना चाहता हूं और खासकर के डीडीए में जो हमारे साथी हैं क्योंकि दिलीप पाण्डेय जी बैठे हैं वो डीडीए में मैम्बर भी हैं सोमनाथ जी तो आज अभी नहीं हैं तो दिलीप भाई से ये प्रार्थना करता हूं कि वो एक ऐसी मीटिंग रखें

जिसके अंदर जो हमारे ऐसे विषय हैं कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको पानी की पाइन लाइन को डलवाने की कृपा करें, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री रोहित कुमार जी।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे अपने त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही गंभीर समस्या को सदन के पटल पर रखने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी पहले भी मैं इस विषय को सदन के समक्ष उठा चुका हूं लगातार जल बोर्ड को लिख रहा हूं न्यू अशोक नगर वार्ड है त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यहां पर एक नाले वाला रोड़ स्थित है लगभग डेढ़ किलोमीटर लम्बा ये रास्ता है जिसके नीचे से जल बोर्ड के तीन नाले गुजरते हैं, drains, aur 100 परसेंट ये covered है जगह सर, लगभग डेढ़ किलोमीटर का ये रास्ता है जोकि यहां पर रहने वाले लोगों की लाइफ लाइन है एक तरह से। सर आप आकर कभी देखेंगे तो वहां पर इतना ज्यादा उबड-खाबड़ और इतना दिक्कतें लोगों को होती हैं निकलने में आने-जाने में और बरसात के दिनों में तो पूरा नर्क हो जाता है। दिक्कत ये है कि जल बोर्ड उसको बनाने के लिये एनओसी नहीं दे रहा है, वो कहता है कि हम इसके ऊपर सड़क नहीं बनाने देंगे सुरक्षा की दृष्टि से लेकिन बड़े ही दिलचस्प बात है कि उसके ऊपर बड़े-बड़े ट्रक गुजरते हैं, जल बोर्ड का खुद टैंकर वहां पर आता है पानी देने के लिये तब वो सड़क नहीं धंसती है लेकिन

बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कितनी बार हमने इसको बनाने का प्रयास किया तो हमेशा जल बोर्ड वहां पर पहुंच जाता है, पुलिस को कम्प्लेंट करता है ।जब मैंने आग्रह किया कि इसको सड़क को बनाया जाये और या उसका कोई विकल्प निकाला जाये तो उल्टा जल बोर्ड ने मुझे धमकी भरा एक लैटर भेजा कि यदि आप इसको जबरदस्ती बनाने की कोशिश करोगे तो अगर कोई दुर्घटना होती हैतो आपको जिम्मेदार माना जायेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने माननीय हमारे जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती जी को लेकर अधिकारियों के साथ में पूरा विजिट किया सोमनाथ भारती जी ने मुझे आश्वस्त कराया कि इसको जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जायेगा और माननीय जल मंत्री जी आतिशी जी यहां पर सदन में बैठी हैं माननीय मंत्रीजी के भी संज्ञान में ये विषय है, माननीय मंत्रीजी भी इस समय इलैक्शन लड़ते हुये कई बार उस रास्ते से गुजरी हैं। तो कितना लोगों की जिंदगी से जुड़ा ये मुद्दा है और बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर इसको लेकर राजनीति भी करते हैं तो माननीय सदन से मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि लोगों की परेशानी को देखते हुये इसको बनाने का कोई ना कोई विकल्प निकाला जाये। जब बारापुला के ऊपर नाला बन सकता है माननीय अध्यक्ष जी जब और जगह के ऊपर नाले बन सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं बन सकता।

माननीय अध्यक्षः रोहित जी हो गया हो गया है।

श्री रोहित कुमारः माननीय अध्यक्ष जी एक और लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है।

माननीय अध्यक्षः इसमें लिखा नहीं है।

श्री रोहित कुमारः नहीं-नहीं इसमें मैं बोल देता हूं उसमें इतनी जगह नहीं है लिखा जाये जो आपका दिया जाता है।

माननीय अध्यक्षः नहीं क्यों नहीं इसके साथ कागज लगाईये पूरा।

श्री रोहित कुमारः नहीं इसमें नहीं लिखा जाता सर इतना इसलिये मैंने शोर्ट में लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो untreated water इसमें भी उसकी भी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिये जो कोंडली STP से जो आता है untreated water जहां से जो शाहरदा ड्रैन में डाला जाता है जो East End Apartment के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि वहां पर जो जहरीली गैसें वहां पर निकलती हैं मिथेन गैस वहां पर निकलती हैं इन्होंने श्रीराम लैब से वहां पर एक जांच कराई जिसमें सैम्पल में सारा स्पष्ट हो गया उसके बावजूद भी अधिकारियों के काम पर जूं नहीं रेंग रही है और मैं ये चेताना चाहता हूं जो जल बोर्ड के अधिकारियों को भी माननीय अध्यक्ष जी कि अगर इसको सड़क को नहीं बनवाया गया तो मैं जल बोर्ड के मुख्यालय पर न्यू अशोक नगर की जनता को लेकर धरना देकर बैठ जाऊँगा और जब तक ये बनेगा नहीं मैं तब तक उठूंगा नहीं वहां से, धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने इस महत्वपूर्ण

विषय को मेरे को उठाने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिये कोई ना कोई समाधान निकाला जाये, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः राजेश ऋषि जी नॉट प्रेजेंट, श्री राजेंद्रपाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी अभी चार-पांच दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संदेशखाली जाने वाले हैं जहां दलित महिलाओं के साथ बहुत ही शर्मनाक अत्याचार की घटना घटी और अभी उस पर शाहजहाँ शेख को गिरफ्तार किया। हम तो वेस्ट बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिये, उनको सज़ा ऐसी मिले जिससे कि इस तरह की घटना करने वाले लोगों को एक संदेश जाये और वो ऐसी घटनाओं से बचें लेकिन मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप संदेशखाली जा रहे हो उसके लिये तो आपका स्वागत है, उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर है जहां पिछले एक साल से मणिपुर की महिलायें लगातार आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपका राह देख रही हैं जिस तरह की भयावह घटना उनके साथ घटी, इस तरह की घटना जिसने पूरे देश को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया ऐसी घटना की विडियो देखकर तो दिल दहल उठता है, शर्म आती है। इस तरह की घटना कभी भी नहीं होनी नहीं जिससे देश की बदनामी हो लेकिन आप केवल

राजनीति मत कीजिये, आप संदेशखाली जाईये और वहां जो दोषी हैं उनको तो सख्त सज़ा होनी ही चाहिये लेकिन साथ में मणिपुर की बहनों से भी मिल आईये उनको भी थोड़ा मरहम लग जायेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मणिपुर में कोई सरकार है ही नहीं तो वहां की राज्य सरकार तो पूरी तरह फेल है ही है, वहां तो सिपाही वहां नीचे बंदूकें रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं चूंकि वहां एक एएसपी को उन्होंने बंधक बना लिया यानि पुलिस का मनोबल सेना का मनोबल गिर रहा है लेकिन आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री संदेशखाली जा रहे हैं अभी बीएचयू गये थे छात्र छात्राओं से मिले थे बड़े जय जयकार के नारे लगे थे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जिन बीजेपी आईटी सैल के तीन दरिंदों ने बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी गये लेकिन उस पीड़िता बहन से भी मिल आते उसको भी थोड़ा मरहम लग जाता लेकिन वहां आप हर जगह केवल राजनीति करते हैं। आप देखिये कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तीन दिन पहले शाम को एक जगह थी जहां कूड़ा डलता था और वहां हमारे समाज के लोगों ने एक बोर्ड लगाया था कि वहां कूड़ा ना डले और उस बोर्ड में बाबा साहेब का फोटो बना हुआ था वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जाकर खुलेआम उसके सर में गोली मार दी।

माननीय अध्यक्षः भई अब, गौतम जी, गौतम जी ये इसमें नहीं लिखा है।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः माननीय अध्यक्ष जी उसके सर में गोली मार दी इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिये गौतम जी, सुरेंद्र जी ऐसे नहीं वो बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः आप लोग वनफूलपुरा में गोली चला दी है ऐसे गोली मार रहे हो। वनफूलपुरा के अंदर आपने मॉइनॉरिटी के लोगों के अंदर गोली मार दी। लोगों के मकान गिरा रहे हो, हमारे लोगों की जान क्या इतनी सस्ती है। मैं चाहता हूं कि सोमेश को न्याय मिलना चाहिये। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मिलख तहसील के अंदर रामपुर के उस गांव के अंदर सीधे उसके सिर में गोली मारकर बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को मार दिया गया, क्या वहां की पुलिस गुंडों का साथ दे रही है? मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने देश के उन यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जिनके बारे में हमारे विपक्ष के नेता अक्सर यशस्वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनका यश कहां चला जाता है जहां दूसरी सरकार है वहां तो वो तुरंत जाते हैं।

माननीय अध्यक्षः गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः जहां सरकारें बीजेपी की हैं वहां भी कुछ जरा।

माननीय अध्यक्षः गौतम जी सब्जैक्ट से बाहर इस पर जो नहीं लिखा हैं।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः ये भी इसके अंदर है, आप देखें मैं पढ़ देता हूं कहो तो इसको पूरे को। लास्ट-लास्ट कर रहा हूं दो मिनट लास्ट।

माननीय अध्यक्षः हां लास्ट करिये करिये।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो निवदेन करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक बार उस बिलकिस बानो बहन से भी मिल आईये, गुजरात के अंदर जहां आपकी सरकार के तहत जब आप मुख्यमंत्री थे वहां सामूहिक बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि उनके परिवार के अनेकों लोगों की हत्या कर दी गई और उसमें जो दोषी थे, जिनको कोर्ट ने सज़ा दे दी उनको तो आपकी वहां की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया था, वो तो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उन्होंने न्याय देने का काम किया। अगर आप बिलकिस बानो से जाकर मिलेंगे उनको भी कुछ मन को राहत मिलेगी, उनको भी कुछ आप जाकर मिलकर उनको सांत्वना दीजिये।

माननीय अध्यक्षः चलिये हो गया, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस उम्मीद के साथ किदेश के प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। देश की प्रजा आपको

प्रधानमंत्री मानती है, आप सबको एक ही नजरिये से देखिये और सबके साथ न्याय कीजिये। जिसका भी उत्पीड़न हो उन सबके साथ आप खड़े होईये, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र South Extension Part -2 के ब्लॉक-बी और आर दोनों ब्लॉकों में पानी की अत्यंत गंभीर समस्या है। वहां पानी की सप्लाई बहुत कम है और सप्लाई कम होने के साथ-साथ सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि पानी के टैंकर जो कभी पानी की सप्लाई शॉर्ट सप्लाई को दुरूस्त करने के लिये पानी की सप्लाई करते थे वो दिल्ली जल बोर्ड ने ूपजीकतूं कर लिये हैं। ऐसे में ना पानी आ रहा है और ना पानी सप्लाई करने के टैंकर उपलब्ध हैं, वहां लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस पूरे के पूरे क्षेत्र में पानी की बहुत गंभीर समस्या है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से नम्र निवेदन है कि कृपया महोदया South Extension Part -2 के जो बड़ी पोश कॉलोनी है सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज्यादा अच्छे टैक्स पेयर के जगह अगर पानी की सप्लाई कम हो और लोगों को अगर पानी के लिये दिक्कत आये, वहां ट्यूवेल लगा नहीं सकते NGT की गाइडलाइंस हैं personal tube well लगा नहीं सकते, सरकार पानी नहीं दे पा रही है वहां और जो पानी का जो सेकेंडरी साधन था उसको सरकार के दिल्ली जल बोर्ड के विभाग ने withdraw

कर लिया है तो मेरी नम्र निवेदन है महोदया आपसे कि कृपया एक तो पानी की सप्लाई ठीक करायें दूसरा जो टैंकर हैं उनकी उपलब्धता करायें क्योंकि पूरे क्षेत्र में कभी भी पानी की सप्लाई हरियाणा की मेहरबानी से कभी-कभी हम पानी की समस्या से जुझते हैं, कभी-कभी हम अमोनिया बढ़ता है कभी शॉर्ट सप्लाई होती है तो ऐसे मैं जरूरी है कि पानी के टैंकर्स की भी उपलब्धता हो जिससे शॉर्ट टर्म के लिये जब भी कभी ऐसी eventuality हो तो लोगों को पानी के लिये बहुत ज्यादा दिक्कत ना पड़े। दिक्कत इतनी आती है कि लोग बिसलेरी का पानी टॉयलेट मे यूज़ करने के लिये मजबूर होते हैं। तो ये हमारा जो सरकार का भरोसा था कि लोगों को 20 हज़ार लीटर हम मुफ्त देंगे उसको पूरा करने में कहीं-कहीं दिल्ली जल बोर्ड का विभाग जान-बूझकर ऐसी circumstances पैदा कर रहा है कि लोगों को एक अच्छी सरकार को बदनाम करने का मौका मिले, मुझे लगता है ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। पानी के टैंकर्स की सप्लाई रोक देना एक जानबूझकर उठाया हुआ कदम लगता है जिससे लोगों को और लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा प्लीज़ आप इसको दिखवाईये, थैंक्यू सर।

माननीय अध्यक्ष: श्री पवन शर्मा जी।

श्री पवन शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधानसभा के जल बोर्ड के कामों की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले लगभग 8-10 महीने से जहांगीर पुरी एच-ब्लॉक मंगल बाजार रोड़ पर पानी की लीकेज हो

रही है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है पिछले हफ्ते माननीय उपाध्यक्ष श्री सोमनाथ भारती जी ने भी राउंड लिया, निरीक्षण किया वहां पर और आश्वासन भी दिया कि जल्द ही एक-दो दिन में काम शुरू हो जायेगा लेकिन अध्यक्ष जी अधिकारियों को बोलते हैं तो वो बोलते हैं बजट नहीं है तो मेरा आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से जल मंत्री जी बैठी हैं हमारे सामने कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाये या कोई प्रावधान 1 करोड़ रुपया विधायक का जल बोर्ड में चला जाता है हर साल, कोई ऐसा प्रावधान भी किया जाये कि ऐसी इस प्रकार की कोई अगर पँस जाता है कोई काम तो 20-30 लाख रुपया विधायक, विधायक फँड से और देकर एक्स्ट्रा विधायक फँड से कम से काम करवा दे, लोगों की गालियां तो कम से कम ना मिलें हमें तो अध्यक्ष जी, सारे सीवर भरे पड़े हैं अधिकारियों को बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारी गाड़ी हटा ली गई है पानी के टैंकर हटा लिये गये हैं तो हर रोज़ नई-नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी कृपया जो है मेरी समस्याओं पर थोड़ा विचार करें और प्रयास करें मेरी समस्याओं का हल निकले, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज गोविंद जी। माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर देना चाह रही हैं।

माननीय जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): ये कई महीनों से पूरी दिल्ली भर में समस्या चल रही है कि जो सीवर और पानी के

लिये लेबर लगे हुये थे कॉन्ट्रैक्चुल लेबर लगे हुये थे उनको दिल्ली जल बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था। जो मशीनें थीं सीवर क्लीनिंग मशीनें उनके से काफ़ियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इनको contractually use किया जाता है काफ़ियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किये गये। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर कई विधानसभाओं में गई हूं, राजेश गुप्ता जी के यहां गई हूं, जरनैल सिंह जी के यहां गई हूं, रोहित महरोलिया जी के यहां त्रिलोकपुरी में गई हूं और काफी दबाव बनाने के बाद ही वहां पर काम हो रहे थे। इसका मूल कारण तो जो हम पिछले कुछ दिनों से इस विधानसभा में चर्चा करते आ रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर सरकार के सारे काम रोके जा रहे हैं। आप सबको पता है कि पिछले 7 महीने से दिल्ली जल बोर्ड को फाइनांस डिपार्टमेंट की बदौलत एक रुपया भी रिलीज़ नहीं हुआ है लेकिन मुझे सभी विधायकों को ये बात बताते हुये खुशी है कि जो आपकी सीवर मशीनों की और लेबर की समस्या है उसका समाधान दिल्ली जल बोर्ड ने अपने ही रेवेन्यु से किया है और सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो लगे हुये थे और जो मशीनें लगी हुई थीं उनको फिर से रखने का आदेश दे दिया गया है उन सबके टैंडर प्रोसेस में हैं पूरी दिल्ली में। तो मुझे उम्मीद है कि जो सीवर के ओवरफ्लो की समस्या है इसका समाधान आने वाले दो से तीन हफ्तों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो जायेगा।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदया जी कल 29 तारीख थी कोर्ट में है उसका कुछ जानकारी में है।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी, कल जज साहब किसी tribunal में बैठे हुये थे तो उन्होंने फर्स्ट हाफ में जब हमारा मैटर लगा हुआ था तो वो कोर्ट में थे नहीं हमने इसकी नतहमदज उमदजपवदपदह करी थी हमारे दिल्ली सरकार के standing counsel ने सैकेंड हाफ में जब वो आये थे, तो उन्होंने मंडे को हमारे दिल्ली जल बोर्ड के मैटर को फर्स्ट मैटर के तौर पर अपने कोर्ट में लिस्ट किया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस के जरिये 280 में ही हमने एक मसला बहुत पहले उठाया था कि पूरे किराड़ी क्षेत्र के अंदर में एक रेलवे फाटक है जिसमें वहां की 8 लाख आबादी जो है जाकर के सुबह और शाम अटक जाती है पांच-पांच घंटे का जाम होता है और मुझे बताते हुये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने तुरंत संज्ञान लेते हुये उसी वक्त आपने एमसीडी को भी बुलाया था और रेवेन्यु ऑफिसर जो डीएम थी उसको भी बुलाया था और उस पर मीटिंग करी थी ताकि इस पर कुछ काम हो सके और अध्यक्ष महोदय मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से की किराड़ी रेलवे फाटक का जो मामला है ये काफी सालों से अटका हुआ है, काफी सालों से

यही चल रहा है कभी एमसीडी बनायेगी, रेलवे बनाएगी कभी बोलते होते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रहा है और सबसे बड़ा मज़ाक 26 फरवरी को होता है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लिस्ट बनाते हैं देखिये ये लिस्ट है मेरे हाथ में कि देश भर में इतने ROBs जो रेलवे पर जो railway over bridge है उसका प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे उसमें किराड़ी का नाम भी है 12-C फाटक है 12-C किराड़ी, दिल्ली पूरा कागज़ लेकर आया हूं मैं, समझ रहे हैं लिस्ट किया जाता है रेलवे डिपार्टमेंट तैयारी करती है भाजपा वाले ढ़िढोरा पिटते हैं कि प्रधानमंत्री जी 133 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे जो है उस पर ROB बनायेगी। हमें खुशी हुई हमने कहा कि हर मैटर राजनीति करने का नहीं होता है, जनता का समाधान हो रहा है, जनता ने वोट दिया है दो-दो बार इनके प्रधानमंत्री को, सांसद को जिताया है तो कम से कम कुछ तो मिल रहा है, हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। सबसे बड़ा मज़ाक क्या होता है अध्यक्ष महोदय की इस पर हरियाणा का नाम है, उत्तर प्रदेश का नाम है सब जगह पर शिलान्यास हुआ अंत मोमेंट पर एक दिन पहले हमारा जो 12-C है उसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और आप देखिये किराड़ी के 8 लाख लोगों को पहले तो बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया लास्ट में जो है उसका शिलान्यास की लिस्ट से नाम हटा दिया और अब क्या कहते हैं भाजपा के नेता अब जा जाकर लोगों को ये कहते हैं कि केजरीवाल ने एनओसी नहीं दिया शिलान्यास करने का। मतलब आरओबी रेलवे बना रही है, रेलवे की जमीन पर बना रही है उसकी खुद की

प्रॉपर्टी है, केन्द्र सरकार की है, प्रधान मंत्री कर रहे हैं शिलान्यास और उनको एनओसी केजरीवाल से चाहिए, राज्य सरकार से चाहिए। मतलब झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, इतनी गंदी राजनीति। अरे प्रवासी लोगों से क्यूं नफरत करते हो। पहले रामलीला मैदान में खड़ा होकर बोला कि साढ़े सत्रह सौ कालोनी जो है कच्ची कॉलोनी है इसको पक्का करेंगे, पक्की रजिस्ट्री देंगे। आज मतलब पांच साल हो गया, पांच लोगों को पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली पूरी दिल्ली के अंदर में। पांच लोगों को नहीं मिली। एक करोड़ से ज्यादा लोग कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। मैं बताता हूं पांच लोग मेरे को ला करके दे दो जिनको पक्की रजिस्ट्री दी हो डीडीए ने। xxxxxx[1] असत्य बोलते हैं। उसके बाद शिलान्यास की ये लिस्ट देखो। इसमें से लास्ट में गायब कर देते हैं। केवल इस लिए क्योंकि हम बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। हम को अधिकार नहीं है बुनियादी सुविधाओं का और किराड़ी और दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कच्ची कॉलोनी के लोगों को चुपचाप खाली मोदी के नाम पर तुम लोकसभा में वोट देते हो और अंत में मोदी जी आपके साथ क्या करते हैं, देखो ये। बिहार में भी वोट मत करना इस बार। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत पीड़ा हुई है हमें जानकरके ये बात। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तक ये बात पहुंचे कि ये सालों से 35 सालों से एक रेलवे फाटक का समाधान नहीं कर पा रहे। दस-दस साल से xxxxxx[1]

---

[1]चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

बैठे हुए हैं और ऊपर हम प्रवासी लोगों के साथ ये मजाक करते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए बैठिये। ये ऋतुराज जी के भाषण में से 'प्रधान मंत्री', 'झूठ' शब्द हटा कर असत्य कर दीजिए। श्री सुरेन्द्र कुमार जी। भई मैं बोल रहा हूं। नम्बर आयेगा मैं बोलता हूं। मैने और ले रहा हूं सबको।

श्री सुरेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मौका देने का दिया आपके लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको अपनी विधान सभा गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र के सबोली वार्ड हर्ष विहारकी ओर दिलाना चाहता हूं। मेरी विधान सभा गोकलपुर के अन्तर्गत आने वाले हर्ष विहार सबोली वार्ड दिल्ली सरकार का एक भी मोहल्ला क्लीनिक अभी निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यहां आम जनता को बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैने विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की है लेकिन अभी तक यहां पर कोई मोहल्ला क्लीनिक नियमित प्रक्रिया शुरू हो नहीं हो पाई। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो मेरे इन दोनों वार्ड में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के तहत आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोलने की प्रक्रिया शुरू करें तथा यहां पर बड़ी डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी जनसख्या वाला इलाका है जिसके लिए वहां एक बड़ी डिस्पेंसरी की बेहद आवश्यकता है। यह जनसंख्या

निम्न वर्गीय गरीब लोग रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे दोनो वार्डो हर्ष विहार, सबोली में मोहल्ला क्लीनिक एवं आधुनिक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी खोलने का आदेश करें जिससे कि मेरी विधान सभा की स्वास्थ्य समस्या को निजात मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से जो संस्कृत पाठशाला चल रही है और उसमे जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी तरफ ध्यानाकर्षण चाहूंगा। प्रत्येक राज्य में संस्कृत पाठशाला के लिए या गुरूकुल के लिए बोर्ड बनाया गया है लेकिन दिल्ली में कोई संस्कृत का बोर्ड नहीं है और यहां की पाठशाला तथा संस्कृत गुरूकुलों ने दिल्ली के बाहर से मान्यता ली है। परन्तु 2004 के बाद बाहर के बोर्ड से भी मान्यता नहीं मिल पा रही है। 2006 में डाक्टर गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान गठित किया गया था जो वर्तमान में भाषा मंत्रालय के पास है और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि दिल्ली सरकार के द्वारा इसको मान्यता दी जाये। वर्तमान में छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा की तो परीक्षा हो रही है लेकिन दसवीं और बारहवीं का समकक्षता नहीं मिल पाया है। इसके लिए मैंने हमारे शिक्षा मंत्री जब मनीष जी थे उनको हमने कहा भी था और उन्होंने चिट्ठी लिखी भी थी अधिकारियों को कि इस पर काम करें और इसका बोर्ड का गठन करें। लेकिन

इस पर कुछ हो नहीं पाया। अभी 2004 से पहले जितने भी स्कूल थे संस्कृत पाठशाला हैं, उनको अनुदान मिल रहा था। वो छः ऐसे पाठशाला थे जिसको अनुदान मिल रहा था। लेकिन उसमें भी तीन पाठशाला बंद हो गये केवल तीन ही पाठशाला है। 2004 के बाद दस से अधिक पाठशाला खोले गए। लेकिन ना तो उसको अनुदान मिल रहा है ना मान्यता मिल रहा है। मेरे बुराड़ी में भी श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम् करके इब्राहिमपुर मे एक पाठशाला है, जिसमें लगभग 100 छात्र पढ़ रहे हैं और उसमें ना केवल दसवीं, बारहवीं बल्कि वेदों की पढ़ाई हो रही है, दर्शन की पढ़ाई हो रही है और बड़े ही अच्छे से वहां के बच्चे वेद पाठ और दर्शन में काम कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये ही निवेदन है माननीया शिक्षा मंत्री भी बैठी हुई हैं कि ये जो संस्कृत पाठशाला है उसका जो एग्जाम आठवीं का, दसवीं का या इसके ऊपर जो एग्जाम है उसको मान्यता दी जाए और ये सब अपने आप चंदा इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सरकार जो अनुदान दे रही थी छः पाठशालाओं को उसी तर्ज पर अब जितने पाठशाला हैं उसको अनुदान की व्यवस्था की जाए वर्ना ये सब पाठशाला बंद हो जायेगे। इसको कोई उचित व्यवस्था करें ताकि ये सभी पाठाशाला चल पाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 280 में मेरे क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का और

बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं पिछले काफी समय से परिवहन मंत्री जी और विभाग को पत्र भी लिख रहा हूं और मैने पर्सनली भी कई बार कहा है कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारी बसें जो पहले चलती थी, 521, 580, 680, 512, 423, 419 ये बहुत कम कर दी गई है और अम्बेडकर नगर देवली दोनों विधान सभा साथ-साथ है। संगम विहार यहां पर कई लाख लोग डेली ट्रेवल करते हैं। बहुत ही इकॉनोमिकल क्लास से ये लोग आते हैं। बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जो बसों में सफ़र करते हैं। बस की कमी की वजह से लोग कई-कई घंटे तक बस स्टॉप पर खड़े रहते हैं तो मेरा आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि बस की सुविधाएं ज्यादा बढ़ा दी जायें और पहले विराट तक बल्कि 580 एक बस स्टेंड हैं वहां तक काफी सारी बसें आती थी वो भी आना बंद हो गई है। तो मेरा अनुरोध आपके माध्यम से है कि उन बसों को पुनः चालू करायें और पुष्प विहार के अंदर काफी समय से पुष्प विहार एक पूरा वार्ड था जिसमें कई हजार सरकारी कर्मचारी रहते हैं और बहुत कई किलोमीटर का वो क्षेत्र है। उसमें ना तो कोई बस की सुविधा है। रोड बहुत चौड़े हैं तो उसमें भी बस की सुविधा पहले 501 बस वहां चलती थी वो पुनः चलाई जाए और मैट्रो फीडर बस बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैट्रो फीडर बस भी चलाई जाए। क्योंकि अभी तीन नए मैट्रो स्टेशन एक साकेत, मालवीय नगर और एक चिराग दिल्ली बन गया है जो कि अम्बेडकर नगर और पुष्प विहार से करीबन तीन से पांच

किलोमीटर दूरी पर है और मैट्रो फीडर बस अगर वहां रहेगी तो सभी पुष्प विहार के निवासियों को अम्बेडकर नगर, दक्षिणपुरी, मदनगीर, तिगडी खान पुर इन सब निवासियों को इन बसों से और मैट्रो फीडर से सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष जी आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्याओं पर बोलने का मौका दिया। आपका दिल से धन्यवाद, आभार।

माननीय अध्यक्षः श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी आज मैं अपने क्षेत्र के दिल्ली देहात के दो पुश्तैनी गांवों की समस्या आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र में मसूदपुर गांव आता है, किशनगढ़ गांव आता है। अध्यक्ष जी, मसूदपुर और किशनगढ़ गांव में आये दिन पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें डेमेज होती रहती है। हम काफी बार एक-एक लाइन करके उसको चेंज करवाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोगों को गंदा पानी आता है कभी सीवर के मेन होल से पानी की लाइनें चली जाती है इस वजह से या वो पुरानी लाइनें गल चुकी है इस वजह और सीवर के जितने भी मेन होल है वो भी लगभग सारे ही खराब हैं जिसकी वजह से गांव के जो मकान है उनके अंदर सीपेज जा रही है, उनको डेमेज होने का खतरा है। तो अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, जल मंत्री से ये यह अनुरोध करूंगा कि ये हमारे ये दोनों गांव मसूदपुर और किशनगढ़ गांव का एक कम्पलीट प्लान

बनाकर क्योंकि बीच-बीच में हम पैसा लगाते हैं उस पैसे का ज्यादा लाभ नहीं होता। थोडे दिनों बाद वो लाइन भी खराब हो जाती है। तो एक कम्पलीट प्लान की एक बार में मसूदपुर गांव की सारी पानी की लाइनें बदली जाए एक ही बार में सारे सीवर बदले जायें उसके बाद वो रोड खुद जायेंगे और सारे रोड्स एक बार बना दिया जाए। उसके बाद में अध्यक्ष जी इन दोनों गांवों का ये दोनों काम होने के बाद में मुझे नहीं लगता बीस साल तक भी सीवर और पानी की वहां पर समस्या आयेगी। तो मेरी ये आपके माध्यम से जल बोर्ड और माननीय मंत्री और वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती जी से निवेदन है कि इस तरह का प्लान गांव के दिल्ली देहात के गांव के लिए बनाया जाए। थोडा-थोडा काम करके अध्यक्ष जी वो सारा पैसा भी खराब होता है और वो समस्या हल भी नहीं होती। बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। मेरे लेट आने के बाद भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। एक घंटा पूरा नहीं हुआ है, 19 माननीय विधायकों ने अपना 280 पूरा कर लिया है। सदन शान्तिपूर्वक चले। अब माननीया वित्त मंत्री महोदया श्रीमती आतिशी जी दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत करेंगी और अपना वक्तव्य भी देंगी।

माननीया वित्त मंत्री (श्रीमती आतिशी): अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण रखने से पहले मैं आपको और सदन को ये सूचना देना चाहती हूं कि कुछ दिन पहले जैसा मैनें बताया था कि बजट

बनने में कुछ विलम्ब हुआ था इसलिए एमएचए में भेजने में हमें थोड़ी देरी हुई थी लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि बजट एमएचए से वापिस भी आ गया है। उसके बाद सीएम साहब के माध्यम से एलजी साहब से अप्रूव होकर वापिस आ गया है तो चार तारीख को यानि सोमवार को मैं बजट यहां पर सदन में प्रस्तुत कर दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं।[2] अध्यक्ष महोदय, अक्सर जब आर्थिक सर्वेक्षण जो इकॉनोमिक सर्वे है जब ये सदन पटल पर रखा जाता है तो सिर्फ इसे टेबल कर दिया जाता है। इसकी डिटेल्स में भाषण नहीं दिया जाता। अपनी पूरी बात नहीं रखी जाती। लेकिन मैं आज एक खास कारण से कुछ बातें इकॉनोमिक सर्वे की इस सदन पटल पर रखना चाहती हूं। आपके सामने रखना चाहती हूं और वो कारण है जो पिछले कई दिनों से पिछले हफ्ते दस दिन से जब से हमारा सदन चल रहा है तो रोज-रोज हम किसी एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जल बोर्ड का काम रोक दिया गया, किस तरह से अस्पतालों का काम रोक दिया गया। किस तरह से मोहल्ला क्लीनिक्स का काम रोक दिया गया। तो जिस साल का ये इकॉनोमिक सर्वे है, 2023-24 ये एक ऐसा साल रहा है केजरीवाल सरकार का जहां पर केन्द्र सरकार ने, उनके एलजी साहब ने और उनकी धमकियों के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों ने केजरीवाल सरकार के काम रोकने में कोई भी कसर नहीं छोडी इस 2023-24 के साल में।

[2] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23264 पर उपलब्ध।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहां पर बैठे हैं, सौरभ भारद्वाज जी। वो आपको बतायेंगे कि किस तरह से दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक में कई महीनों तक 2022 में दवाईयां रूक गई, टैस्ट रूक गए, मोहल्ला क्लीनिक के बिजली बिल के बिल नहीं दिये, डाक्टरों की तनख्वाह नहीं दी गई, उनका किराया नहीं दिया गया। एक समय ऐसा था अध्यक्ष महोदय जब मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर खुद तनख्वाह ना पाने के बावजूद सारा बिजली का बिल अपनी जेब से दे रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी दिल्ली में। अस्पतालों की ओपीडी काउंटर से डेटा इंट्री ऑपरेटर्स को हटा दिया गया। जब एक गरीब आदमी इतने बड़े अस्पताल में आता था उसे पता ही नहीं चलता था कहां जाना है कि कहां पर cardiologist बैठता है, कहां पर ईएनटी स्पेशलिस्ट बैठता है, कहां पर paediatrician बैठता है। तो वो अस्पताल में दर-दर की ठोकरें खा रहा था। दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम को रोक दिया गया। जैसा कि आप जानते है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा तक के भी रिसर्च फैलोज को हमारे एलजी साहब द्वारा हटा दिया गया। विधायकों के काम रोकने के लिए दिल्ली सरकार के काम रोकने के लिए। आठ साल के कानूनी संघर्ष के बाद चाहे हाई कोर्ट में हों, चाहें सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे constitution bench के सामने हो दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार के हक में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक तरफा फैसला दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लैड, लॉ एंड आर्डर और पुलिस के अलावा सारी ताकत है, सारी पावर है। लेकिन केन्द्र

सरकार ने केजरीवाल सरकार की ताकत छीनने के लिए उस आठ साल के संघर्ष के बाद आठ दिन के अंदर-अंदर एक अध्यादेश के माध्यम से एक नया कानून लेकर आ गए जो सारी पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीन कर एलजी साहब के हाथ में दे देती है। अध्यक्ष महोदय, इस 2023-24 में अफसरों को जो दिल्ली सरकार के अफसर हैं उन्हें बार-बार डराया गया, धमकाया गया, उन्हें धमकियां दी गई कि अगर चुनी हुई सरकार के साथ काम किया तो तुम पर विजिलेंस इन्क्वायरी कर देंगे, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम पर सीबीआई और ईडी के केसेज लगा देंगे। कई अफसरों के साथ ऐसा किया भी जिससे अफसरों के मन में एक भय बैठ गया कि अगर चुनी हुई सरकार के साथ काम करेंगे तो हमारा अपना कैरियर खराब हो जायेगा। ना सिर्फ अफसर, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्रियों पर, रूलिंग पार्टी के विधायकों पर केन्द्र सरकार ने सीबीआई के केस किये, ईडी के केस किये, तरह-तरह के केस किये। तो जिस साल का ये इकोनोमिक सर्वे अध्यक्ष महोदय आज हम सदन पटल पर रख रहे हैं वो एक ऐसा साल रहा है जहां पर केजरीवाल सरकार के काम रोकने की हर सम्भव कोशिश की गई। लेकिन इकॉनोमिक सर्वे तो देखिये प्योर डेटा है। एलजी साहब चाहे कितनी भी चिट्ठियां लिख लें हमारे मुख्यमंत्री जी को कितनी भी गालियां निकाल लें कि तुमने कोई काम नहीं किया दिल्ली में लेकिन आखिरकर डेटा तो डेटा है और आज ये 2023-24 का जो इकॉनोमिक सर्वे का डेटा है वो दिखा रहा है कि पिछले एक वर्ष में इनकी हर

सम्भव कोशिश के बावजूद दिल्ली की अर्थ व्यवस्था, दिल्ली की इकॉनोमी 2023-24 के साल में एक रिकार्ड चंबमपर बढ़ी है। ये इकॉनोमिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले एक साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ये इकॉनोमिक सर्वे ये दिखा रहा है दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। ये इकॉनोमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है fiscal surplus में रहा है। ये दिल्ली का इकोनोमी सर्वे है। तो आज मैं सदन पटल पर इस इकॉनोमिक सर्वे के साथ अपना वक्तव्य इस लिए रख रही हूं कि मैं चाहती हूं कि केन्द्र सरकार उनके एलजी साहब ये जान लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें केजरीवाल रूकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं और जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का विकास रूकेगा नहीं। दिल्ली वालों की जिंदगी का जो बेहतरी का प्रयास ये सरकार कर रही है वो प्रयास रूकेगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस इकॉनोमिक सर्वे में जब हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि जो दिल्ली का जीएसडीपी है current prices के अनुसार 2022-23 में दस लाख चौदह हजार करोड़ था, लेकिन एक रिकार्ड 9.17 परसेंट ग्रोथ दिखाकर 2023-24 में ग्यारह करोड़ सात हजार करोड़ तक पहूंच गया है। ये केजरीवाल सरकार की एचीवमेंट है। जब दिल्ली की इकॉनोमी देश की इकॉनोमी के साथ 2021-22 में कोविड के दौरान contract हुई थी तो दिल्ली ही एक इकलौता राज्य है जिसने

2021-22 में आठ परसेंट के रेट पर और 2022-23 में 7.85 परसेंट के रेट पर रियल जी.एस.डी.पी. ग्रोथ दिखाई है जो पूरे देश में कहीं पर देखने को नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में देश की डेढ़ परसेंट आबादी रहती है। लेकिन सिर्फ डेढ़ परसेंट आबादी होने के बावजूद दिल्ली का देश के जीडीपी में 4 परसेंट की हिस्सेदारी है ये है केजरीवाल की सरकार। ना सिर्फ इतना अगर हम पिछले दो साल के आंकड़े देखने जायें तो 2021-22 में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय तीन लाख सत्तर हजार रूपये के आसपास थी और मात्र दो साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय चार लाख इकसठ हजार पर पहूंच गई है, यानि दो साल में 22 परसेंट बढ़ी है। ये जो प्रति व्यक्ति आय है ना सिर्फ इसने एक रिकार्ड ग्रोथ देखा है पर दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय से ढाई गुणा ज्यादा है, अध्यक्ष महोदय। ये है केजरीवाल सरकार का करिश्मा। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन में भारत देश में अगर दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो हैं मंहगाई और बेरोजगारी। आज भारत का जो मंहगाई दर है, जो inflation rate है वो पूरी दुनिया में दूसरे नम्बर पर है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक टर्की देश है जिसमें मंहगाई भारत से ज्यादा है। पिछले दस सालों में हमारे देश में 70 परसेंट से ज्यादा मंहगाई बढ़ी है। हर आम इंसान को पता है कि 2014 से लेकर आज तक 2014 में गैस सिलेंडर 300/-रूपये का होता था आज 1200/-रूपये पर पहूंच गया है। पैट्रोल का दाम 72/-रूपये से 100/-रूपये पर पहूंच गया है, डीजल का दाम 55/-रूपये

से 90/-रूपये पर पहुंच गया है। देश में मंहगाई का दर 2023 में 5.65 परसेंट था जो मुझे लगता है कि पिछले देश के 75 साल के इतिहास में शायद इतना मंहगाई दर नहीं रहा। लेकिन केन्द्र सरकार के ही आंकड़े अध्यक्ष महोदय ये दिखातें है कि अगर पूरे देश में सबसे कम मंहगाई दर किसी राज्य में है तो वो दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में है। जब केन्द्र सरकार का जनवरी से दिसम्बर 2023 से मंहगाई दर 5.65 परसेंट था दिल्ली मंहगाई दर उसका आधा मात्र 2.81 परसेंट था, पूरे देश में सबसे कम मंहगाई दर। दूसरी देश की सबसे बड़ी समस्या अध्यक्ष महोदय है बेरोजगारी। बेरोजगारी पिछले कई सालों से अपनी चरम पर है। अगर आप नेशनल लेवल का अन-एम्पलाईमेंट का डेटा देखें तो 5.65 परसेंट अन-एम्पलाईमेंट आज देश में है। अगर युवाओं का ही आंकड़ा देखने जायें तो वो और भी भायवह है कि आज हमारे देश में 25 परसेंट युवा बेरोजगार हैं। अगर आप ग्रेजूऐट्स का आंकड़ा देखने जाइये तो वो उससे भी बदतर है कि आज हमारे देश में 42 परसेंट ग्रेजूऐट बेरोजगार हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ना सिर्फ दिल्ली में लोगों को रोजगार दिलाया पर दिल्ली में business opportunity भी बढ़ाई जिसकी वजह से एम्पलाईमेंट opportunities बढ़ी हैं। दिल्ली में 2020-21 में अन-एम्लाईमेंट रेट रोजगारी का दर 6.3 परसेंट था लेकिन पिछले दो सालों में कोविड के बाद फिर से इकॉनोमी को जो फिलिप देने का बूस्ट देने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। 2020-21 में 6.3 परसेंट के

अन-एम्पलाईमेंट रेट पर 2022-23में यह आंकड़ा मात्र 1.9 परसेंट पर आ गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकारी राजस्व के बारे में और जो हमारा बजट है सरकार का उसके बारे में आंकड़े रखूंगी। मैं जब ये आंकड़े देख रही थी इकॉनोमिक सर्वे जब कम्पलीट हुआ तो मैं याद कर रही थी कि जब हम 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे तो हमारा एक चुनावी नारा था, बिजली हॉफ, पानी माफ और उस समय लोग हम पर हंसा करते थे। वो कहते थे जी अरविंद केजरीवाल ऐसे ही सपने दिखाता है ये सम्भव नहीं है कि वास्तव में बिजली हॉफ हो जायेगी, पानी माफ हो जायेगा और जो लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है सब्सिडी देकर कर लेंगे बिजली हॉफ, पानी माफ उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की अर्थ-व्यवस्था तो उसके राजस्व को डूबो देंगे। सारा सरकारी खजाना खत्म कर देंगे, इन लोगों से सरकार नहीं चलेगी। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय हम सबके लिए जो इस सदन में बैठे हैं ये गर्व की बात है कि अगर आज पूरे देश में एक सरकार है जो वो मुनाफे में चलती है fiscal surplus के साथ चलती है वो दिल्ली सरकार है। अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार है। 2021-22 में दिल्ली का रेवेन्यु सरप्लस 3270 करोड़ था और 2022-23 में ये बढ़ के 14,450 करोड़ हो गया कि इतना खर्च करने के बाद भी जितना हमारा खर्चा है उससे ज्यादा राजस्व दिल्ली सरकार के पास है, उससे ज्यादा रेवेन्यु दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली सरकार ने 2022-23 में अपने राजस्व में 18 परसेंट की वृद्धि को देखा है और ना सिर्फ इतना जैसा मैंने आपको कहा कि दिल्ली

सरकार इस देश की एक मात्र मुनाफे में चलने वाली fiscal surplus वाली सरकार है और इसका कम्पैरिजन में केंद्र सरकार से रखना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। आज की जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो वास्तव में उधारी की सरकार है। 2014 से ले के 2024 तक के अगर आप आंकड़े देखिए 2014 में हमारे देश का डैट 55 लाख करोड़ था, यानि आजादी से ले के 2014 तक 55 लाख करोड़, लेकिन मात्र 10 साल में वो 155 लाख करोड़ हो गया है, यानि देश की उधारी 3 गुना बढ़ गयी है। एक आंकड़ा होता है इकोनोमिक सर्वे में debt as percentage of GDP यानि हमारे देश के जीडीपी का कितना हिस्सा वास्तविक तौर पे उधारी है, डैट है जो हमें वापस करना है। 2014 में ये आंकड़ा था 67 परसेंट लेकिन पिछले 10 साल में ये बढ़के 92 परसेंट हो गया है तो आज देश का 92 परसेंट जीडीपी का हमारा डैट का हिस्सा है और इसके विपरीत दिल्ली में अध्यक्ष महोदय जो एक fiscal surplus बजट की मैं बात कर रही हूँ एक मुनाफे के बजट की मैं बात कर रही हूँ ये हमें पिछली सरकारों से नहीं मिला है। पिछली सरकारें डैट लेती आई थी, लोन लेती आई थी। अपने राजस्व से ज्यादा खर्चा करती आई थीं तो इसलिए जब दिल्ली में हमारी अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार बनी तो काफी उधारी दिल्ली सरकार पर भी थी तो एक आंकड़ा होता है अध्यक्ष महोदय ratio of interest payment to revenue receipts यानि कितनी उधारी दिल्ली सरकार पर है कि जितना राजस्व है उसमें से कितना परसेंट हिस्सा हमें उधारी चुकाने में

उसका इन्ट्रैस्ट चुकाने में देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय 2012-13 में ये आंकड़ा ratio of interest payment to revenue receipts 11.2 percent था, लेकिन अरविन्द केजरीवाल जी ने जितनी समझदारी के साथ ये सरकार चलाई है ये आंकड़ा 11.2 परसेंट से घटकर आज मात्र 5.2 परसेंट रह गया है। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपनी उधारी को समाप्त किया है, कम किया है फिर भी इतनी शानदार सरकार चलाई है। अध्यक्ष महोदय दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, बस यात्रा फ्री देती है, अच्छी शिक्षा फ्री देती है, स्वास्थ फ्री देती है, मोहल्ला क्लीनिक और अस्पताल में हर इलाज फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती है फिर भी मुनाफे की सरकार चलाती है। हमने एक स्टडी करवाई थी हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तो उन्होंने दिल्ली के साढ़े तीन हजार परिवारों के साथ सर्वे किया। उस साढ़े तीन हजार परिवारों के सर्वे में ये निकलकर के आया कि तकरीबन उसमें से ऑलमोस्ट 100 परसेंट परिवारों को कभी ना कभी दिल्ली सरकार की इलैक्ट्रीसिटी सब्सिडी का फायदा हुआ है। चाहे वो 200 यूनिट फ्री हो, चाहे वो 400 यूनिट पे 50 परसेंट की सब्सिडी हो। 75 परसेंट लोगों को फ्री पानी का फायदा मिला है हमारी स्टडी में निकल के आया। 65 प्रतिशत लोगों ने फ्री ट्रीटमेंट या तो सरकारी अस्पताल में या मोहल्ला क्लीनिक में करवाया। 58 परसेंट परिवारों की महिलायें दिल्ली सरकार की फ्री बस यात्रा की सुविधा लेती हैं और 44 परसेंट परिवार दिल्ली सरकार के शानदार सरकारी स्कूलों में अपने

बच्चों को भेजकर अपना पैसा बचाते हैं। तो हर महीने हर परिवार का हजारों रूपए दिल्ली सरकार की पॉलिसियों की वजह से बचता है। अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है कि इन सब सुविधाओं के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, राजस्व बढ़ रहा है। मैं तो इस सदन को ये बताना चाहूंगी कि इन सब सुविधाओं की वजह से ही दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। दिल्ली का विकास हो रहा है। आप देखिए कि हर परिवार में बिजली फ्री, पानी फ्री और बस का किराया फ्री स्वास्थ्य फ्री हजारों रूपए हर परिवार के हर महीने बचते हैं अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार की वजह से। ये कहां जाता है पैसा? ये पैसा, आंकड़े ये दिखाते हैं, हमारी स्टडी ये दिखाती है कि उसमें से तकरीबन 62 परसेंट जो परिवार हैं वो उसे जमा करके नहीं रखते, वो उसे खर्च कर देते हैं। चाहे खाने का सामान खरीदने में, चाहे अपने बच्चों को किताबें दिलावाने में, चाहे अप्लाइंसिस खरीदने में, चाहे फ्जि खरीदने में, चाहे एसी खरीदने में तो ये डेढ़ हजार करोड़ रूपए से ज्यादा दिल्ली की अर्थव्यवस्था में घूमता है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को liquidity देता है। हम law of supply and demand की बात करते आये हैं हमेशा से अपने इकोनोमिक्स में तो जो अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार ने सब्सिडीज देकर दिल्ली वालों की जेब में पैसा डाला है उन्होंने इकॉनोमी में डिमांड क्रियेट की है जिसके माध्यम से अब लोग बाजार में सामान खरीद रहे हैं उनकी एक्सपेंडिचर करने की योग्यता बढ़ी है और ये ही कारण है कि अगर आप कोविड के जो economy shrink हुई,

जो डिप्रेसन आया इकॉनोमी में दिल्ली की रिकवरी की स्पीड सबसे ज्यादा रही अरविन्द केजरीवाल जी सरकार की इन पॉलिसीस की वजह से। अध्यक्ष महोदय जैसा कि आप जानते हैं अब हमारा 9 बजट केजरीवाल सरकार इस सदन में प्रस्तुत कर चुकी है। 10वां बजट आने वाला है। हमारे बजट में हर बार सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन एक चौथाई हम शिक्षा को देते हैं और इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई जो हर स्टेट के बजट का एनालेसिस करती है और उस आरबीआई की स्टेट बजट एनालेसिस की रिपोर्ट ने ये दिखाया कि 2022-23 में अगर हम सारे राज्यों ने कितना व्यय किया। कितना एक्सपेंडिचर किया तो दिल्ली सरकार ने पूरे देश की सरकारों में से सबसे ज्यादा व्यय शिक्षा पे किया 21.1 परसेंट किया, जबकि पूरे देश में औसत मात्र 13.5 परसेंट है। हमारे बोर्ड रिजल्ट्स के आंकड़े आये, आईआईटी, जेईई के आंकड़े ये तो अक्सर हम रखते ही हैं सदन में लेकिन आज में एक और आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहूंगी कि दिल्ली की gross enrollment ratio यानि कितने बच्चें हैं जो दिल्ली में स्कूल में पढ़ रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं जब बच्चों को स्कूल भेजने की बात आती है तो स्कूल के शुरूआती सालों में तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है। लेकिन जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो अक्सर एक गरीब माता-पिता को लगता है कि भई कुछ पढ़ तो रहा नहीं है, कुछ सीख तो रहा नहीं है, नौकरी तो मिलनी नहीं है तो इसको स्कूल से बाहर

निकालकर काम ही करवा लूं, दो पैसे ही कमा लेगा। लेकिन अगर और मुझे लगता है कि आंकड़ा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितना सुधार आया है इस बात को दिखाता कि ना सिर्फ दिल्ली का gross enrollment ratio प्राइमरी स्कूल्स में हाई है, लेकिन सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल में यानि 11वीं, 12वीं में जबकि पूरे देश में 57.05 परसेंट ही बच्चे 11वीं, 12वीं तक पहुंचते हैं दिल्ली में ये आंकड़ा 95 परसेंट हैं। इसका मतलब जो बच्चे स्कूल में घुसते हैं नर्सरी में पहली कक्षा में वो अपनी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई करके ही बाहर निकलते हैं। वो ड्रॉप आउट नहीं होते, शिक्षा व्यवस्था से बाहर नहीं होते। अध्यक्ष महोदय हमारा इकॉनोमिक सर्वे ये भी दिखाता है कि केजरीवाल सरकार ने 16.17 परसेंट खर्चा पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे किया। दिल्ली में हेल्थ पे बहुत infrastructure है अध्यक्ष महोदय। वो दिल्ली सरकार का भी है, एमसीडी का भी है, प्राइवेट भी है जिसमें 92 हॉस्पिटल्स, 39 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 1650 डिस्पेंसरीज, 124 मेटरनिटी होम्स, 46 पॉलिक्लिनिक्स, 1000 नर्सिंग होम्स हैं, लेकिन इस पूरे आंकड़े में से एक बड़ी संख्या दिल्ली का जो पूरा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रैक्चर है वो केजरीवाल सरकार का ही है। आज केजरीवाल सरकार के पास 38 मल्टीस्पेशलटी और सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल्स हैं। 521 मोहल्ला क्लीनिक हैं, 175 डिस्पेंसरीज हैं, 60 प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, 30 पॉलिक्लिनिक्स है, 55 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं, 25 यूनानी डिस्पेंसरीज हैं और 117 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं। अध्यक्ष महोदय ना सिर्फ हमने अच्छे स्वास्थ्य की

व्यवस्था की व्यवस्था दी है लेकिन अब आंकड़े देखिए कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको इंडीकेटर माना जाता है कि आपकी ओवरऑल शहर का, आपके राज्य का हेल्थ क्या है तो अगर आप एक ऐसा आंकड़ा माना जाता है infant mortality rate कि आपके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका mortality रेट कितना है, क्योंकि उससे माता का स्वास्थ्य कैसा है, आपकी हेल्थ केयर फेसिलिटीज कैसी हैं वो सारे फिचर्स फेसिलिटीज उसमें रिफ्लैक्ट हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय पूरे देश का infant mortality rate का आंकड़ा 2.8 परसेंट है लेकिन दिल्ली का उसका आधे से भी कम है। मात्र 1.2 परसेंट। पूरे देश में neo natal mortality rate 2 percent है दिल्ली का उससे आधे से कम 0.9 परसेंट है। पूरे देश में under five mortality rate बच्चों का 3.2 परसेंट है दिल्ली का उसका एक तिहाई है 1.4 परसेंट। यानि हम अपने बच्चों को उनकी माताओं को सबको अच्छे स्वास्थ की सुविधा दे पायें। अब मैं पावर सेक्टर पे आती हूँ अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय कॉपनहेगन बिजनेस स्कूल ने कुछ साल पहले एक स्टडी करी थी और उन्होंने बताया था कि एक घण्टा एक्स्ट्रा बिजली देने से आप भारत में किसी गरीब परिवार की आय 15 परसेंट तक बढ़ा देते हैं क्योंकि जब बिजली आती है बच्चे पढ़ पाते हैं आप अप्लायंसिस यूज कर पाते हैं, आप इंटरनेट की फेसिलिटीज यूज कर पाते हैं और मुझे खुशी है इस बात है केजरीवाल सरकार पिछले 9 साल से लगातार दिल्ली वालों को 24 घण्टे बिजली दे रही है। 2013-14 में दिल्ली की पीक डिमांड

5650 मेगावाट थी। ये 2022-23 तक आते-आते 7700 मेगावाट पहुंच गयी, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार ने ये बिजली दिल्ली वालों को बिना किसी पावर कट के बिना किसी लोड सेडिंग load shading के लगातार दी अध्यक्ष महोदय। ना सिर्फ इतना जो एटीएनसी लॉसिस होते हैं जो बिजली की चोरी होती है वो 2012-13 में 16 परसेंट था पिछले 10 सालों में एक तिहाई हो गया है। मात्र 6 परसेंट रह गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को जीरो बिल दिये हैं और 2022-23 में 3 करोड़ 40 लाख जीरो बिजली के बिल दिल्ली में साल भर में दिल्ली वालों के आये हैं। पानी की सप्लाई पे भी लगातार काम हुआ है। केजरीवाल सरकार ने 20 किलो लीटर पानी मुफ्त देने का वायदा किया था, दिया भी है। 25 लाख कन्ज्यूमर्स को इसका फायदा मिला है। ना सिर्फ पानी फ्री दिया है अध्यक्ष महोदय हमारे यहां पे कई साथी हैं जिनके इलाकों में बहुत सारी अनॉथराइज कॉलोनीज हैं। अनॉथराइज कॉलोनीज में पहले ये होता था कि लोग वोट मांगने तो जाते थे लेकिन जब जीतके आते थे तो कहते थे जी यहां पे तो सरकार का पैसा लग ही नहीं सकता। यहां पे एमएलए फँड का पैसा नहीं लग सकता। यहां पे पानी की पाइप लाइन डल सकती। लेकिन पिछले 9 साल में अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार ने अनॉथराइज कॉलोनीज के 97 परसेंट इलाके में पानी की पाईप लाईन डाल दी है। ये मुझे लगता है कि इतनी स्पीड से काम दिल्ली के पूरे इतिहास में नहीं हुआ और अब 94 प्रतिशत जो household हैं

दिल्ली के उनके पास पाईप वाटर सप्लाई का एक्सेस है। दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी भी बढ़ी है। आज दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी 630 एमजीडी पे पहुंच गई है। जलबोर्ड का 10 हजार किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क branch सीवर नेटवर्क है और 200 किलोमीटर तक ट्रंक सीवर नेटवर्क है। अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसकी अक्सर मुझे लगता है कि हम बात कम करते हैं लेकिन हमारी अचीवमेंट्स इस सेक्टर में बहुत ज्यादा हैं और वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। किसी भी शहर के विकास में, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं, अपनी टू व्हीलर्स नहीं हैं लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए अपना बिजनेस करने के लिए उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। आज अध्यक्ष महोदय दिल्ली सरकार ने बसों के और मेट्रो के माध्यम से इतना बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दिया है कि डेली एवरेज पैसेंजर राइडरशिप अगर हम देखें तो दिल्ली की जो डीटीसी बसेस हैं उसमें 25 लाख राइड्स पर डे दिल्ली वाले लेते हैं। क्लस्टर बसेस में 16 लाख राइड्स पर डे और दिल्ली मेट्रो में 46 लाख पैसेंजर्स डेली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हर रोज 87 लाख पैसेंजर्स दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं चाहे स्कूल जाने के लिए, चाहे कॉलेज जाने के लिए, चाहे अपने बिजनेस के लिए और सिर्फ इतना ही नहीं आज दिल्ली की टोटल बस fleet 7 हजार 500 पार कर गई है जिसमें

से 1650 इलैक्ट्रिक बसें हैं और हम सबको इस बात पे भी बहुत गर्व है कि अगर आप पूरी दुनिया में इलैक्ट्रिक बसों का बेड़ा देखने जाइये तो दिल्ली का बेड़ा ऑलरेडी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सिर्फ एक चाइना का शेन्जन शहर है और सेंटीयागो हैजो दिल्ली से आगे है लेकिन हमारे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने इतनी सारी इलैक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दे दिया कि कुछ ही महीनों में हम पूरी दुनिया में नंबर वन पर पहुंच जायेंगे इलैक्ट्रिक बसेस के मामले में। पिंक टिकट के माध्यम से हमने महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी और 2022-23 में टोटल नंबर ऑफ पिंक टिकट 45 करोड़ था। 45 करोड़ बार हमारी माताओं और बहनों ने बस यात्रा की। सिर्फ इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय अक्सर दिल्ली को यहां पे होने वाले प्रदूषण की वजह से काफी criticism का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां पर भी दिल्ली सरकार ने कई प्रयास किये हैं। 2022-23 में केजरीवाल सरकार ने 70 लाख से ज्यादा पौधे एक साल में लगाये हैं और सिर्फ इतना ही नहीं जो दिल्ली का फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो एक आंकड़ा होता है कि इसकी डेन्सिटी कितनी है तो आज दिल्ली की 23.06 परसेंट एरिया ग्रीन कवर में आता है जो देश के किसी भी शहर से ज्यादा है और ये लगातार पिछले 10 साल में बढ़ता आया है। ना सिर्फ इतना जो एक्यूआई में गुड डेज माने जाते हैं उसका आंकड़ा 2018 से बढ़ा हैं। 2018 में 158 एक्यूआई के अनुसार गुड डेज थे जो 2023 तक 206 तक पहुंच गया है। तो अध्यक्ष महोदय जो हमारा इस बार का

इकोनोमिक सर्वे दिल्ली के विकास की, दिल्ली के लोगों की जिंदगी के बेहतरी की गाथा सुना रहा है मैं आज उस इकोनोमिक सर्वे के माध्यम से जो सब लोग के अरविन्द केजरीवाल जी का विरोध करते हैं उनके काम को रोकने की कोशिश करते हैं मैं उनको बताना चाहूंगी एक बार फिर कि आप कितनी भी बाधायें डालते रहिये अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को एक वादा किया है कि वो उनकी जिंदगी को बेहतर बनायेंगे और हमारे विरोधी कितनी भी कोशिश करते रहें लेकिन अरविन्द केजरीवाल जी अपना वादा पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण जून साहब ने एक बड़ा दर्दनाक विषय यहां रखा था। एडिश्नल कमिश्नर, कार्पोरेशन ने विधायकों को चोर बताते हुए जो लेटर एलजी को लिखा था उस पर उस दिन विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था उसका प्रथम प्रतिवेदन आज प्रस्तुत हो रहा है। श्री संजीव झा जी, मैं यहां ये भी बता दूं कि सोमनाथ भारती जी इस कमेटी के चेयरमेन थे उनको संसद का टिकट मिलने के कारण वो व्यस्त हैं। कल संजीव झा जी को इस कमेटी का चेयरमेन नियुक्त किया गया है। उसका प्रथम प्रतिवेदन संजीव झा जी प्रस्तुत करेंगे। श्री संजीव झा जी और अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ[3] और अगर चाहे तो मैं कुछ डिटेल अगर सदन जानना चाहे चूंकि कल ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एमसीडी के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और इंजीनियरिंग चीफ को बुलाया गया था। और सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। जून साहब ने जो चिट्ठी सदन के सामने नोटिस सौंपी थी उसपे कमिश्नर साहब से सवाल-जवाब किया गया और कमिश्नर साहब ने इसपे अनकंडिशनल एपोलोजी उन्होंने इस सदन को किया है। उनका ये कहना था कि ये चिट्ठी जिस एडिशनल कमिश्नर ने निर्गत किया उनका अब ट्रांसफर यहां से हो चुका है। तो कमिश्नर होने के नाते इसमें जो शब्द है वो वास्तव में ठीक नहीं है और मैं इसके लिए अनकंडिशनल एपोलोजी सभी सदस्यों से और हाउस से लेता हूँ। साथ में एनओसी को लेकर चर्चा हुई थी तो कमेटी ने रिकमेंड किया है कि एक कोईनोडल पर्सन बना दिया जाए और नोडल पर्सन 48 घंटे के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी एजेंसी एक्जीक्यूटिव एजेंसी अगर एस्टीमेट करती है तो एस्टीमेट करने से पहले एमसीडी में एनओसी के लिए लिखे और 48 घंटे के अंदर वो एनओसी दे। उन्होंने कहा है कि हम विदिन वीक इसको बनाकर के नोडल पर्सन हम सदन को सूचित कर देंगे। साथ में तीसरा जो बड़ा ईशु था वो था लाईट को लेकर के भी ईशु था कि जो लाईट लगे हुए हैं वो मेंटेंन नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहां-जहां

[3] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23265(1-2) पर उपलब्ध।

ये दिक्कतें हैं वो एमसीडी उसको तत्काल संज्ञान में लेगी। ये मोटी-मोटी जो रिक्मन्डेशंस थे ये रिक्मन्डेंशन मैं सदन के सामने सब साथियों को बताना चाह रहा था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा नियम-55 के अंतर्गत अखिलेशपति त्रिपाठी जी। डीडीए, एएसआई, एलएनडीओ एवं रेलवे जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दिल्ली में गरीबों के घरों को ध्वस्त करने के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने दिल्ली के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले उन तमाम लोगों के लिए आवाज उठाने का अवसर दिया, चर्चा करने का अवसर दिया सदन में। अध्यक्ष महोदय हर एक आदमी का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो जहां पर वो रहकर के अपने बच्चों का अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाये। शाम को जब काम से आये तो थक कर के उस घर में थोड़ा-सा आराम कर पाये। अध्यक्ष महोदय, वो गरीब लोग जिन्होंने दिल्ली को खड़ा करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने श्रम से, अपने काम से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है। उन लोगों के सपनों पर कुठाराघात करते हुए लगातार केंद्र की सरकार अपने अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से उनको दिल्ली से बाहर करने का कुचक्र रच रही है। अध्यक्ष महोदय, तुगलकाबाद में

जून का महीना तपती गर्मी का महीना दो जून 2023 को तकरीबन दस हजार लोगों को उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनको तपते धूप में जलने के लिए छोड़ दिया गया और ये काम किया एएसआई ने जो केंद्र सरकार की ऐजंसी है। अध्यक्ष महोदय इस मामले में कई बार कोर्ट के स्टे भी रहे, उसको भी दरकिनार कर दिया। तो जैसा हम लोग कहते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार अपनी सरकार चला रही थी। कोर्ट ने कह दिया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार चलाने का पावर अरविंद केजरीवाल जी को होगा। उस कोर्ट के आदेश को रददी की टोकरी में डाल दिया और उन्होंने एक कानून पास कर दिया कि एलजी सरकार चलाएगें। एलजी बॉस होगें ऐसे ही इस मामले में हुआ। कोर्ट के आदेश के बावजूद झुग्गी को गिरा दिया गया यहीं पर कारवां नहीं रूका अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 24 अगस्त 2023 को सुभाष कैम्प बदरपुर में तीस साल से यहां पर लोग रह रहे थे जिसके वहां पर रहने का बिजली का बिल उन के लोगों के पास था, गैस के कनैक्शन थे लोगों के पास, राशनकार्ड था लोगों के पास, वोटर आईडीकार्ड था लोगों के पास। ये घटना जो लीडर आफ ओपोजीशन है उनके क्षेत्र में हुआ। तो आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से केन्द्रीय ऐजेंसीयों का प्रयोग करके झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को दिल्ली से खत्म करने का, उनके जीवन को खत्म करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये लीडर आफ ओपोजीशन के एरिए में सुभाष कैम्प में हुआ और इसमें तकरीबन, अध्यक्ष

महोदय बताना चाहता हूं तकरीबन 8 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अध्यक्ष महोदय, ये यहीं पर नहीं रूके ये भैरों मार्ग पर प्रगति मैदान वहां पर जी–20 के नाम पर इन्होंने कोर्ट का स्टे आदेश होने के बावजूद भी वहां पे लगभग 300 झुग्गी झोंपड़ी को तोड़ने का काम किया जिसमें तकरीबन पांच छह हजार लोग प्रभावित हुए। आगे बढ़ते हुए डीडीए ने किशन गंज में वहां पर भी जो है झुग्गी झोंपड़ियों को डिमोलिश करने का काम किया। अभी राजेश बैठे थे अभी चले गए। हम लोग लगातार चर्चा करते रहे बगल का हमारे लोगों का सटा हुआ एरिया है। डीडीए उनके क्षेत्र में लगातार झुग्गी झोंपड़ियों के डिमोलिशन का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक अलग अलग घटनाओं में 50 से अधिक झुग्गी झोंपड़ी कलस्टर्स को गिराने का काम केन्द्र की सरकार ने कर दिया है जिसमें पांच हजार से ज्यादा घरों को गिराया गया है और तकरीबन तीन लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए क्योंकि इस तरीके की घटना से ना केवल दिल्ली में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी उन लोगों को बहुत धक्का लगा है जिन लोगों ने अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से सींच कर के दिल्ली को खड़ा किया है चाहे यहां के भवन निर्माण की बात हो वहां काम वही करते हैं, चाहे डोमेस्टिक लेबर के रूप में काम करने की बात हो उन्हीं के घर के लोग काम करते हैं, चाहे कहीं ड्राइवर का काम करना हो, उन्हीं के लोग काम करते हैं। पेपर हॉकर के रूप में

काम करना है वो ही लोग काम करते हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन है इस जो कुचक्र केन्द्र की सरकार रच रही है उसको रोकने के लिए तत्काल सदन कार्यवाही करे। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेंद्रपाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुददा उठाया है। लोग कितने मुश्किल से घर बनाते हैं और घर बनाना इतना आसान काम नहीं है बहुत मंहगा काम हो गया है। पहले तो जमीनें बहुत मंहगी हैं और फिर कन्सट्रक्शन कॉस्ट उससे भी ज्यादा है। दिल्ली की विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वो आया नगर हो, किशन गंज हो, सुभाष पार्क हो सोनिया विहार हो इस तरह के अनेक क्षेत्रों में कहीं पे आरकलोकिजकल सर्वे आफ इडिया ने तो कहीं पे डीडीए ने तो कहीं रेलवे ने अनेकों घर उजाड़े हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं केन्द्र की सरकार से कि जितने भी और खास तौर पे माननीय उपराज्यपाल महोदय से भी कि जितने भी ये झुग्यिां तोड़ी जा रही हैं, जो कच्ची कालोनियां तोड़ी जा रही हैं या क्लस्टर्स जहां जहां बने हैं उनको तोड़ा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं जिस वक्त ये कालोनियां बसी उस वक्त ये विभाग कहां सोए हुए थे। ऐसी जगह पर भी गरीब आदमी कैसे कैसे कर्ज करके बीस गज के, तीस गज के, पैंतीस गज के, पचास गज के प्लाट खरीदता है। अपने

पूरे जीवन की कमाई लगाता है और कर्जा ले के फिर उसको बनाता है। अगर वो अवैध थे, अगर वो Archaeological Survey of India की जमीन पर थे, अगर वो फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर थे अगर वो रेलवे की जमीन पर थे, अगर वो डीडीए की जमीन पर थे तो जब वहां कालोनियां कट रही थी जो colonizer गरीबों से खून चूसकर पैसे लेकर वो कालोनियां काट रहे थे उस वक्त आपकी पुलिस क्या कर रही थी, उस वक्त जो अपने आपको land owing ऐजेंसी बता रहे हैं कि हम मालिक हैं इसके ये अवैध कालोनी है उस वक्त वो विभाग कहां थे, उनके अधिकारी कहां थे, उस वक्त पुलिस के अधिकारी एसएचओ वो कहां थे। मुझे आज भी याद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जहां भी कहीं अवैध कालोनी बनेगीं उसके लिए जिम्मेदार वहां के एसएचओ और एसडीएम होगें। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि इस देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कोई वैल्यू है या नहीं है और अगर वैल्यू है तो मैं केन्द्र सरकार के इन विभागों से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मांग करता हूं, निवेदन करता हूं वो बताएं आज तक कितने एसएचओ को इस तरह की अवैध कालोनियां बसने देने में मदद करने में, पैसे की वसूली में उनको जिम्मेदार ठहरा के उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन शुरू किया गया। कितने ऐसे एसडीएम हैं या दूसरे अधिकारी हैं इन विभागों के जिनके रहते हुए वो कालोनियां कटीं, वहां मकान बने और उन्होंने उसे रोकने की बजाय वहां पर पैसे ले के उनको बनने दिया। उन

गरीब लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने कैसे कैसे करके ये मकान बनाए थे आपने झटके में उनके मकान तोड़ के उनको रोड़ पे ला दिया। एक शायर ने लिखा था–

''लोग टूट जाते हैं इक घर बनाने में

किंतु कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में''

ये तो बस्तियां उजाड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा वक्‍कूल पुरा के अंदर वहां जिस तरह मकान तोड़े गए, लोगों पे गोलियां चलाकर लोगों को मारा गया। उसी तरह इस तरह की जो गरीब बस्तियां हैं जितने भी ये झुग्गीयां तोड़ी गई हैं या जहां भी अनओथराइज कह के मकान तोड़े गए हैं अगर इसका एक सर्वे हो जाए तो पता चलेगा कि ये ज्यादातर लोग गरीब मजदूर खासतौर पर दलित पिछड़े माइनोरिटी के लोग जिन लोगों ने यहां आ के दिल्ली में मजदूरी करके कैसे कैसे पैसा जोड़ा, कैसे कैसे ये प्लाट खरीदे, जब ये प्लाट कट रहे थे तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? वहां उनकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो आफिसिस हैं उसके बाहर जो दलाल बैठते हैं वो बाहर ही वो जो जीपीए वगैरह बना दिया करते हैं आज तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? जितने भी इस तरह की कालोनियां बनी हैं आप देखेंगे ज्यादातर के पास पेपर मिलेगें, उस पर नोटरी पब्लिक के मोहर लगी मिलेगी, साइन मिलेगें। ऐसे कितने नोटरीज के खिलाफ कार्यवाई हुई। मैं तो ये जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय इस तरह एलजी साहब को और

केन्द्र सरकार के इन विभागों को लोगों के घर उजाड़ने की बजाय लोगों के घरों को बसाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री वैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का गुणगान पूरे देश में करते घूम रहे हैं। मेरे ख्याल सैंकड़ों करोड़ रूपया उसके उपर खर्च कर दिया उन्होंने प्रचार के उपर तो ऐसी किसी भी बस्ती को उजाड़ने से पहले वो बताएं क्या उन्होंने उन बस्तियों को उजाड़ने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उनको मकान दिए क्या? आप उनको रोड़ पे ला रहे हो यहां तक कि कड़कती ठंड के अंदर लोगों को उजाड़ दिया। ये बेहद शर्मनाक है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और उपराज्यपाल जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि वो कहते हैं मैं हैड आफ द स्टेट हूं दिल्ली का, मैं मालिक हूं, मैं हूं सरकार। आप सरकार हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर अवैध कालोनियां बन रहीं हैं तो फिर आप जिम्मेदारी ले लो इस्तीफा दे दो अपने पद से चूंकि आपके रहते बन रही है, आपके अधिकारी बनवा रहे हैं, आपके अधिकारी पैसे ले रहे हैं, लगातार कब्जे होते जा रहे हैं तो वहां जहां कब्जे हो रहे हैं, नई नई कालोनियां बन रही हैं, सरकारी जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, डीडीए की जमीन पे डूसिब की जमीन पे, हम चिटिठयां लिख रहे हैं कि ये अभी नए नए कब्जे हो रहे हैं इनको रोकिए। नए अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको रोकिए।

(समय की घंटी)

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः तो जो हम कंपलेंट कर रहे हैं उस पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही और जो गरीब तीस साल से चालीस साल से 50 साल से 60 साल तक के पुराने मकान तोड़े गए हैं अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है कि अभी कोई दस दो चार दिन में दो चार महीने में या पांच सात साल में बने हैं जिनको 50-50, साठ साठ साल हो गए, चालीस साल तीस साल इतनी पुरानी कालोनियों को तोड़ा है जबकि कानून भी ये कहता है adverse possession का अधिकार देता है लोगों को कि अगर लोग लंबे समय से सरकारी जमीन पर अगर तीस साल से ज्यादा समय से uninterruptedly रह रहे हैं तो ऐसे मकानों को तोड़ा नहीं जाता by way of adverse possession वो मालिक बन जाते है।

...व्यवधान...

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः नहीं नहीं वो अभी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दूसरी आ गई है मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। मैं तो इस बात पे जा रहा हूं कि जब ये कालोनियां बनती हैं।

माननीय अध्यक्षः कनकलूड करिए राजेंद्र जी, प्लीज कनकलूड करिए।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः तब ये विभाग कार्यवाई क्यों नहीं करते हैं, तब पुलिस कार्यवाई क्यों नहीं करती है, तब एलजी साहब कार्यवाई क्यों नहीं करते हैं? तो इसके लिए जांच बिठाकर जितनी भी ये कालोनी कब कब बसी, कौन तोड़ने वाले, कौन बसवाने

वाले उनको भी प्रोसीक्यूट करके उनको सजा दी जाए। अगर उनको सजा नहीं दी गई जो पुलिस अधिकारी वहां रहे हैं मौजूद जिस वक्त ये कालोनियां बनी हैं या जितने वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी रहे हैं जब ये कालोनियां बसी हैं या जिन जो विभाग अपने आप को मालिक कह रहे हैं उन विभागों पे जब ये कालोनियां बसी थीं जो अधिकारी उस वक्त मौजूद थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको प्रोसीक्यूट किया जाए और जिनको विस्थापित किया किया गया है, जिनके मकान तोड़े गए उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकानों का आवंटन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री प्रवीन देशमुख जी।

श्री प्रवीण कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय एक पुरानी पंक्तियां हैं-

''जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं

वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें गरीबों के प्रति प्यार नहीं।''

भारतीय जनता पार्टी इन गरीबों को उजाड़कर एक तरीके से दुष्टों का काम कर रही है और गरीबों की हाय लेने का काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले 21, 22, 23 नवबंबर 2023 को मेरे क्षेत्र में एक संदर नर्सरी डीपीएस मथुरा रोड़ एक जे.जे. क्लस्टर है उस जे.जे. क्लस्टर्स में करीबन 400 झुग्गियां थीं और उन 400 झुग्गियों को निर्मम तरीके से बुलडोज़र के

माध्यम से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। हजारों लोग वहां पे रहते थे जो भरे ठंड के मौसम में अब सड़कों पे आ चुके हैं। और वो सिर्फ उस समय नहीं रहते थे वो पिछले 40 सालों से वहां पे रहते थे और एकाएक जो है वो पूरी बस्ती को उजाड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की शह पे एल एंड डी ओ द्वारा किया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक वर्ड है डे लाईट रोबरी। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उनके केंद्र सरकार के द्वारा उनके डिपार्टमेंट के द्वारा ये डे लाईट रोबरी का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एलजी के माध्यम से उनकी शह पे किया गया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये जिस क्लस्टर की मैं बात कर रहा हूं ये क्लस्टर जो है वो नोटिफाईड 675 क्लस्टर्स में है जो ड्यूसिब की पॉलिसी है 2015 की, उसमें ये क्लस्टर्स को प्रोटेक्शन दी गयी है कि बिना रिहैबिलीटेशन के इन क्लस्टर्स को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बावजूद ये 675 की लिस्ट को इग्नोर करते हुए एल एंड डी ओ द्वारा इस सुंदर नर्सरी को पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया और ये भी बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये 675 की लिस्ट है इसमें 223 नंबर का जो क्लस्टर है वो सुंदर नर्सरी डीपीएस मथुरा रोड है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब ये केस जो कोर्ट में चल रहा था जोकि एक छोटे से एंक्रोचमेंट का चल रहा था। किस तरीके से एल एंड डीओ द्वारा पूरा केस घुमाया गया और पूरा केस जो है वो तीन तीन बुलडोज़र लाके वहां पे सुंदर नर्सरी पे खड़े करे गये, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अध्यक्ष

महोदय ये हुआ है। और जबकि ये भी मैं सदन पटल पे ये कहना चाहता हूं कि वो जो लैंड है खसरा नंबर 484 जो लैंड है उस लैंड का टाईटल अभी तक क्लियर नहीं है। उसका सूट जो है वो माननीय उच्च न्यायलय में चल रहा है जिसमें वक बोर्ड और एल एंड डी ओ के बीच जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में ये खसरा नंबर उसमें है मौजूद। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये भारतीय जनता पार्टी की शह पे सारे चीजों को दरकिनार करते हुए एल एंड डी ओ द्वारा पूरी तरीके से उस क्लस्टर को नष्ट कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तो उच्च न्यायलय द्वारा एक वर्बल आर्डर दिया गया जो 20 नवम्बर को दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक ये डिसिजन नहीं होता तब तक जो है इस क्लस्टर को नहीं तोड़ा जाये लेकिन उसके बावजूद एल एंड डी ओ डिपार्टमेंट द्वारा और सारे इनके केंद्र सरकार के महकमे पुलिस, ये वो सारे तामझाम के साथ लगातार वो वहां पे बुलडोज़र चलता रहा वर्बल आर्डर के बावजूद। और जब मुझे ये इँर्मेशन मिली, मैं ग्राउंड पे पहुंचा और ग्राउंड पे मैंने जब वहां पे देखा कि लगातार अभी भी बुलडोज़र चल रहा है, तब मैंने एल एंड डी ओ अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा कि आपको क्या कोर्ट से फोन नहीं आया आपके वकील का, तो वो एकदम से हक्का-बक्का रह गया। उसको मानो सांप सूंघ गया कि ये उसकी साजिश जो है वो फेल हो गयी है। वो पूरी तरीके से सुन्न हो गया और बाकी

अधिकारी वहां पे मौजूद थे, पुलिस के भी थे, उनके चेहरे पे एक तरीके से मातम छा गया। क्योंकि पूरी साजिश जो है, गिद्ध भोज जो है वो पूरी तरीके से वहां पे तहस नहस कर दिया हो। अध्यक्ष महोदय, मतलब कोर्ट के वर्बल आर्डर के बावजूद वो लगातार वहां पे बुलडोज़र चला रहे थे और मैंने वहां पे जाके फिर उसे अधिकारियों को बुला के उससे जब सवाल पूछा तो वो चुप बैठ गया और उसी समय, उस टाईम पे मैंने जो है बुलडोज़र रूकवाया। लेकिन अगले दिन जो है क्योंकि उस समय जो है ग्रैब का नोटिस चल रहा था और ग्रैब थ्री में किसी भी तरीके का डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन जो है अलाउ नहीं था।

(समय की घंटी)

श्री प्रवीण कुमारः अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा समय लूंगा 5 मिनट का और।

माननीय अध्यक्षः 5 मिनट बहुत ज्यादा हैं।

श्री प्रवीण कुमारः दो तीन मिनट में खत्म कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। उस समय जो है ग्रैब थ्री का नोटिस चल रहा था जिसके कारण कोई भी डेमोलिशन, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं थी लेकिन उसके बावजूद इन्होंने डेमोलिशन लगातार करा और जब ये हमने कोर्ट में फाईल करा तो उसके बाद तुरंत जो एक दिन में इनको एग्जम्पशन नोटिस मिल जाता है अध्यक्ष महोदय। तो ये पूरी बहुत बड़ी साजिश जो है ये भारतीय जनता पार्टी की शह पे

चल रही है। इसमें एक और बात और जोड़ना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। जो वहां पे मुगल कालीन एक टॉम्ब था उस टॉम्ब को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया जो गैर कानूनी है अध्यक्ष महोदय जोकि दिल्ली के एएसआई कें प्रोटेक्शन में आता है दिल्ली आर्किआलॉजी प्रोटेक्शन में आता है। उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक और मैं इसमें सिर्फ केंद्र सरकार के अलावा भी किस तरीके से जो दिल्ली सरकार के विभाग हैं उसको भी एलजी के माध्यम से किस तरीके से इँफ्ल्यूएंस किया जा रहा है और गरीबों से बदला किस तरीके से लिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय इसको भी एक छोटे से सवाल के माध्यम से हाईलाईट करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। कुछ दिन पहले विधान सभा में एक प्रश्न लगा था जिस प्रश्न में पूछा गया आपको प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं:

क्या यह सत्य है कि ड्यूसिब के वकील श्री परविन्दर चौहान ने दिल्ली हाई कोर्ट को डीपीएस मथुरा के निकट जे.जे. क्लस्टर नंबर 12 के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी? ये क्वेश्चन जो है वो सदन में लगा था। इसका जानकारी क्या आई। इसका जवाब ये आया कि रिकार्ड के अनुसार रिहैबिलिटेशन ब्रांच के क्रमवार उत्तर में लिखा गया था कि संबंधित जे.जे. क्लस्टर 675 मान्यताप्राप्त जे.जे. बस्ती की सूची में उपस्थित है जोकि 01/01/2006 से पहले अस्तित्व में आ गयी थी परन्तु शपथपत्र जोकि न्यायलय में दायर हुआ था उसमें परविन्दर चौहान अधिवक्ता द्वारा यह नहीं लिखा गया था जोकि

उचित नहीं है। आप देखिये किस तरीके का ष्टाडयन्त्र हो रहा है। मतलब डिपार्टमेंट कह रहा है वकील को जो वहां पे वकील, दलाल ही कह लीजिये, उसको दलाल कहें, दलाल ही है वो, एक तरीके से केंद्र सरकार की दलाली करने के लिये जो वकील खड़ा हुआ है वो वकील जो है जो डिपार्टमेंट उसे कह रहा है कि ये बताओ कि ये मेंशन है, वो अपने एफिडेविट में दायर ही नहीं कर रहा है। वो किसलिये दायर नहीं कर रहा है एलजी के माध्यम से। एक वकील के कारण जो है पूरी तरीके से वहां पे 400 झुग्गियां ढहा दी गयी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एलजी के माध्यम से और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी के माध्यम से इस अधिवक्ता को वहां पे शो कॉज नोटिस इशु हुआ जिसका उसने आज तक जो है वो जवाब नहीं दिया अध्यक्ष महोदय और मैं ये सदन पटल से ये भी मांग करना चाहता हूं कि ऐसे वकील जो लगातार दिल्ली के लिये खतरा हैं और दिल्ली के लोगों के लिये खतरा हैं एलजी ऐसे वकीलों को हटाते क्यों नहीं हैं जिन्होंने पूरी तरीके से न्यायलय में झूठ बोला, ऐसे वकीलों को हटाया क्यों नहीं गया अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः प्रवीन जी अब बैठिये।

श्री प्रवीण कुमारः अध्यक्ष जी, ये बहुत ज्यादा विडम्बना है इस समय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आखिरी में दो लाईन कह के।

माननीय अध्यक्षः प्रवीन जी अब हो गया प्लीज।

श्री प्रवीण कुमारः आखिरी में दो लाईन कह के अध्यक्ष महोदय बहुत गहरी समस्या है ये। आप देखिये नोटिफाईड क्लस्टर को कभी तोड़ा नहीं जाता, डे लाईट रोबरी है अध्यक्ष महोदय। मतलब नोटिफाईड क्लस्टर को तोड़ दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा अति वाली चीज है। आजतक मैंने 10 साल के इतिहास में मेरे कैरियर में कभी नहीं सुना मैंने। अध्यक्ष महोदय, दो लाईन कह के खत्म करूंगा

''कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आयेगा

तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आयेगा।''

अभी खेल लो तुम्हें जितना खेलना है।

माननीय अध्यक्षः जून साहब।

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद सर 28 फरवरी को एक रैट होल माईनर थे वकील हसन जिन्होंने उत्तराकाशी में जब ये टनल में क्राईसिस आया तो 43 लोगों की जान बचाई। 28 तारीख को बिना नोटिस दिये उनके घर को खजूरी खास में डेमोलिश कर दिया। आज पेपर में आया है एलजी साहब भी कह रहे हैं हम इसको आल्टरनेट अकमोडेशन देंगे। क्या आपको पहले नहीं पता था कि ये आदमी कितना अच्छा काम किया था, प्रधानमंत्री जी ने बुला के उसको सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री जी ने भी उनको बुलाया था और एक झटके में सारे जितने भी कानून, उनको दरकिनार करके उस बेचारे का घर गिरा दिया गया। तो कौन राष्ट्र के लिये सेवा करेगा और वो भी एक गरीब आदमी। फिर सर दूसरी बात ये आती है

कि 2018 में एक जजमेंट आया सर लीगल इशु है कि 6 महीने के बाद अगर सिविल या क्रिमिनल केसिज़ में कोई स्टे ग्रांट करती है कोई कोर्ट वो ऑटोमैटिकली वैकेट हो जायेगा 6 महीने बाद। पार्टी को एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं। सर कल एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का फिर आया कि नहीं, हम उस जजमेंट को ओवररूल करते हैं, 6 महीने बाद कोई स्टे वैकेट नहीं होगा ऑटोमैटिकली। ये केस टू केस डिपेंड करेगा। अब सर जो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं अनऑथोराईज कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन चाहे डीडीए का हो, चाहे एएसआई का हो, चाहे लैंड एंड डी ओ का हो, चाहे रेलवे का हो, सर ये जजमेंट इन एजेंसीज़ को फायदा देगा। कोई बिल्डर, कोई रहने वाला वहां जाके स्टे ले आयेगा और वो स्टे फिर सालों तक चलता रहेगा। राजेन्द्र पाल जी ने कहा कि ये एजेंसीज़ क्या कर रही थी क्योंकि सर कोई भी कालोनी, कोई भी बिल्डिंग ओवरनाईट नहीं बन सकती। तो ये एजेंसीज़ काम तो कर रही थी सिर्फ पैसा ऐंठने में। पैसा इकट्ठा कर रही थी ये एजेंसीज़। सर तुगलकाबाद ोर्ट है प्रोटेक्टिड मोन्यूमेंट है एंटायर जो स्ट्रेच है उसके अंदर की, वो सारी बिक चुकी है। उस टाईम एएसआई कहां था। और लोग फिर स्टे भी ले आये। सर हम कहते हुए डरते हैं लेकिन बोल्ड होना चाहिये और कहना चाहिये अगर ये एजेंसीज़ जिम्मेवार हैं तो कुछ हद तक ज्यूडिशियरी भी जिम्मेवार है इस मैलडी के लिये, उसको भी सोचना होगा कि इर्रैशनली स्टे न दें, कोई भी आदमी मिसगाईड करके, डाक्यूमेंट फोर्ज करके, फैब्रिकेट करके स्टे ले आयेगा और वो स्टे

अब सालों चलेगा और ये प्रॉब्लम दिल्ली में बनी रहेगी। स्लम बनाने में सर एजेंसीज नहीं दूसरी कुछ वैसी ऐसी एजेंसीज हैं पुलिस भी है ये एजेंसीज हैं और और बहुत से लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। सर दूसरी बात यह है कि दिल्ली की तरफ क्यों इतना influx है लोगों का Delhi cosmopolitan city है अच्छी बात है और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो डेवलपमेंट की है एडवर्स कंडीशंस के बाद चाहे ऐजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो चाहे, तो जो फेसिलिटीज आज दिल्ली में मिल रही हैं सर, उनको देखते हुए लोग अट्रैक्ट होकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। इकॉनमी बड़ी साउंड है सर per capita income बहुत अच्छी है तो लोग तो आएंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनको नहीं रोक सकते हैं लेकिन जो अथॉरिटीज हैं उनको सोचना चाहिए कि ये जो अनॉथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है या इनको डिमोलिश करने की स्टेज आई तो उनको इनेक्टिव नहीं होना चाहिए इनएक्शन नहीं होना चाहिए उनके पार्ट पर और इमीडिएटली काम करना चाहिए बट गरीब लोगों के पहले। सर दिल्ली हाइकोर्ट ने 2023 में एक जजमेंट आया मैं उसकी चार लाइन पढूंगा। डीडीए का मैटर है 'DDA cannot demolish any house on its own whims and fencies. DDA must issue show cause notice of 15 days and decide the reply of or objection raised by the party before initiating any action. State should follow principles of natural justice.' क्या कोई नोटिस देते हैं 15 दिन का? बिलकुल नहीं देते सर। ये वकील हसन का जो राइट माइनर था इसका घर तोड़ा कोई नोटिस नहीं था।

दूसरी बात यह सर के एएसआई वाले पैसे लेकर बैठ जाते हैं प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं वहां भी कोई कार्यवाही नहीं होती। तो मैं कहता हूं सर लीगली भी सर बहुत सारे flaws हैं जिनका कोर्टों में मिसयूज होता है डिपेंस साइट्स से भी स्टेट काउंसिल जो हैं चुप बैठ जाते हैं जिसकी वजह से ये प्राब्लम चलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर कि अगर इस दिल्ली को स्लम बनने से रोकना है तो अथॉरिटीज को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा और साथ-साथ कोर्ट्स को भी सेंसिटिवली काम करना पड़ेगा। अगर ऐसे काम हुआ तो दिल्ली को स्लम बनने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है मेरी बातें अच्छी न लगें कुछ लोगों को लेकिन सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः श्री सुरेन्द्र कुमार जी।

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, आपने अखिलेश त्रिपाठी के नियम-55 पर बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की विरोधी है और अधिकतर हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली में दिल्ली सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, डिस्पेंसरी की दवाई फ्री, मोहल्ला क्लीनिक तमाम मेरे यहां भी एक झुग्गी-झोपड़ी है वहां हमारी सरकार पूरी सुविधा देने का काम करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय एलजी साहब झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ने का काम करते हैं। अभी एक मेरे यहां सबोली टीला है उस पर अभी करीब 7

बीघे में इन डेढ़-दो साल में डीडीए के द्वारा कब्जा किया गया है। पीछे मैंने एक क्वेश्चन भी लगाया था उसमें 5 बीघे एक नर्सरी वाले ने कब्जा किया कमरा बनाया वहां, पानी का मीटर भी लगवा लिया है, नल भी लगा है पूरी नर्सरी को चलाता है। वो सब पूरी जमीन जो 10 बीघे करीब जमीन है वो डीडीए की है। वो डीडीए ने कुछ हिस्से में झुग्गी-झोपड़ी बसा दी है और कुछ में उस नर्सरी वाले को मालिकाना हक देने का काम कर रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम कोई जमीन मांगते हैं 100, 200, 500 गज एलजी साहब उन पर काम नहीं करते, हमारा डीडीए का वाइस चेयरमैन नहीं सुनता, न लैंड कमिश्नर सुनता कि हमें यहां चौपाल बनाने के लिए जगह दी जाए, या पार्क बनाने के लिए जगह दी जाए, स्कूल या डिस्पेंसरी बनाने के लिए दी जाए। उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केन्द्र की सरकार जरा सा उन पर विचार नहीं करती लेकिन कब्जा कराने में नंबर वन है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये तो एक नारा है जो सरकार जो जमीन सरकारी जमीन गरीबों के लिए है और इन्होंने अभी 2020 में भारतीय जनता पार्टी जब ये चुनाव लड़ी थी दिल्ली सरकार का चुनाव चल रहा था इन्होंने बड़े-बड़े पोस्टर लगाए कहा कि हम जहां झुग्गी वहां मकान बनाएंगे ये तमाम उन्होंने करोड़ों रुपये प्रचार करने का काम किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो एजेंसियां हैं डीडीए हो या रेलवे हो तमाम हमारे गरीबों की झुग्गी-झोपड़ी को तोड़ने का काम कर रही है। तुगलकाबाद हो या अन्य दूसरे हमारे झुग्गी कैंप

हों। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इन झुग्गी-झोपड़ी में अधिकतर 70 परसेंट दलित लोग रहते हैं। 30 परसेंट वो दूसरे समाज के जैसे आपके ओबीसी के रहते हैं माइनॉरिटी के तो अन्य गरीब समाज के लोग भी रहते हैं। उनका टारगेट है कि वो जानते हैं कि ये झुग्गी-झोपड़ी वाले वोट आम आदमी पार्टी को देते हैं इसलिए उनका उजाड़ना चाहते हैं। दिल्ली सरकार उनको पूरी सुविधा देने का काम करती है। दिल्ली सरकार ने अभी इन गरीबों के लिए झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए काफी मकान बनाने का भी काम किया हजारों मकान देने का भी काम किया और मैं आज सीएम साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जहां झुग्गी-झोपड़ी थी वहां मकान बनाने का भी काम किया गया तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है। तो एक संदेश जाता है कि निश्चित तौर से गरीबों के कल्याण की बात नहीं करती कभी भारतीय जनता पार्टी न केन्द्र सरकार करती है और अब तो एक सिस्टम बना रहे हैं एक नया सिस्टम लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अब एक विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा किअब ये जो जाति हैं जो उनके कर्म के आधार पर जो काम करती है जबकि दिल्ली का डेवलपमेंट कराने में इन झुग्गी-झोपड़ियों का जो हमारे मजदूर हैं इस दिल्ली को सजाने-संवारने में काम करती

है लेकिन उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हम शिक्षा पर लोन नहीं देंगे। आप जो कार्य करते हैं यदि कोई लोहार का काम करते हैं 50 हजार लोन लीजिए। आप यदि मोची का काम करते हैं तो आप निश्चित तौर से 50 हजार का काम कीजिए और दूसरा जिसका जाति के अनुसार हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं लेकिन इस विश्वकर्मा योजना के तहत लाकर उन्होंने जातियों को बेवकूफ बनाने का काम किया क्योंकि आज वो जानते हैं कि गरीब लोग शिक्षा लेना चाहते हैं, गरीब लोग आज इंजीनियर बनना चाहते हैं। गरीब लोग आज बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने का काम करते हैं, आईएएस पीसीएस बनने का काम करते हैं। झुग्गी-झोपड़ियों के काफी, मैं अपने क्षेत्र के बताना चाहता हूं मेरे यहां दो बच्चे अभी आईआईटी में दिल्ली सरकार से हमारा 12वी करके गया आईआईटी में उसका एडमीशन हुआ। तो झुग्गी-झोपड़ियों से डॉक्टर-इंजीनियर भी निकल रहे हैं। हमारी दिल्ली सरकार झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों को डेवलपमेंट करने का काम कर रही है उनका विकास करने का काम कर रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन झुग्गियों को तोड़कर इन गरीबों के ऊपर तलवार चलाना चाहती है। आने वाला समय आयेगा इस बार एक-एक वोट आम आदमी पार्टी को देने का काम करेगी। इस बात का संदेश देंगे कि निश्चित तौर से झुग्गी-झोपड़ी का एक-एक वोट आम आदमी पार्टी के साथ है, एक-एक वोट माननीय सीएम साहब के साथ है, आपने मौका दिया धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान दिलीप पाण्डेय जी।

श्री दिलीप पाण्डेयः बहुत-बहुत आभार शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने देने के लिए। बहुत सारे सदन के जिम्मेदार साथियों ने अपनी बात रखी और दिल्ली की 30 प्रतिशत जो आबादी है उनके दर्द को बयान करने की कोशिश की। इस चर्चा के दौरान हमारे गौतम जी ने एक शेर कहा एक जिक्र किया एक दो लाइनों का जिक्र किया। मेरे महबूब शायद हैं बशीर बद्र साहब उनकी लाइनें हैं:

'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में''

बहुत मौजू है बहुत रेलेवेंट और बहुत जरूरी शेर है।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): वाह एक बार और एक बार और।

श्री दिलीप पाण्डेयः अगली बार दूसरा सुनाउंगा लोग टूट जाते हैं, मंत्री जी हैं इनका विभाग है जिस पर चर्चा हो रही है तो इनका आग्रह अस्वीकार नहीं कर सकते।

'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।''

मेरा सौभाग्य रहा है मेरी मुलाकात इनसे हुई है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में केन्द्र की सरकार की जो एजेंसियां हैं चाहे एएसआई हो, चाहे डीडीए हो, चाहे रेलवे हो इन तमाम एजेंसियों ने मनमाने ढंग से न कोई कायदा न कोई कानून मनमाने ढ़ंग से बुलडोजर चलाये और इस अहंकारी बुलडोजर के चलने से पूरी दिल्ली में तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोग मोटा-मोटा जो आंकड़ा है जो मुझे लगता है कि बहुत नीचे की ओर है 50 हजार से भी ज्यादा घर ध्वस्त हुए। इन घरों के टूटने के इमोश्नल aspect को अगर छोड़ भी दिया जाए हम उसे नजरअंदाज भी कर दें तब भी जब इन घरों को तोड़ा जा रहा था किसी कायदे का किसी नियम का किसी प्रोटोकॉल का किसी कानून का अनुपालन नहीं किया गया और साफ-साफ यह दिख रहा था कि केन्द्र की सरकार दिल्ली के अंदर जो गरीब रह रहे हैं जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने का काम करते हैं। ये कार्यवाहियां केन्द्र की सरकार और केन्द्र की सरकारी एजेंसियों की उन गरीब लोगों के प्रति जो नफरत है उसको उजागर करती है। ऐसे एक दो नहीं कई मामले हैं अध्यक्ष महोदय कि जो कायदे-कानून तो एक तरह जो एक महज नोटिस देने की जो औपचारिकता होती है वो नोटिस दिये बगैर भी मकान तोड़ दिये गये हैं जिसका एक हालिया उदाहरण उत्तराखंड में टनल रेस्क्यू टीम को लीड कर रहे वकील भाई जो श्रीराम कालोनी के खजूरी के रहने वाले हैं, मैंने उन्हें बुलाया भी है आज मिलने के लिए मेरी मुलाकात उनसे तय है

उनके मकान को भी ऐसे ही तोड़ दिया गया। आप सोचिये, बड़ा अच्छा एक शेर है बेदिल हैदरी साहब का कि

'मरने के बाद खुद ही बिखर जाउंगा कहीं,

अब कब्र क्या बनेगी अगर घर नहीं बना।''

क्या करूंगा मैं रहके। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया में अपना चेहरा चमकता हुआ दिखाने के लिए जी-20 के दौरान केन्द्र की सरकार और उनके इशारे पर सरकारी एजेंसियों ने लगातार हमारे अनुरोध करने के बावजूद अनुनय-विनय करने के बावजूद कई झुग्गियों पर एक साथ हमला बोल दिया। तब ऐसी शंका नहीं है, ये तयशुदा है कि केन्द्र की इस सरकार को हमारे शहर की बस्ती गंदी लगती है। हकीकत लेकिन इसके दीगर है। हकीकत यह है कि इन बस्तियों से ये शहर साफ है, इन बस्तियों से ये शहर सुकुन से है, इन बस्तियों से ये शहर शहर है। ये बस्तियां न हों, इन बस्तियों में रहने वाले लोग न हों तो उसका असर महलों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा ये हम सब जानते हैं। तब भी इन बस्तियों को तोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रवीण भाई ने जो बात शुरु की उस बात का एक हिस्सा उठाकर आगे जोड़ना चाहूंगा। डूसिब के अंदर प्रवीण भाई ने जिक्र किया 675 बस्तियां जो हैं वो अनुसूचित हैं लिस्टेड हैं। मेरे पास जानकारी है अध्यक्ष महोदय 675 लिस्टेड बस्तियों के अलावा 82 बस्तियां ये कागजात हैं जिनमें 18 अप्रैल, 2023 को डूसिब की जो

बोर्ड मीटिंग हुई उस समय के मंत्री महोदय की अध्यक्षता में उनकी चेयरमैनसिप में उसके नोट्स हैं उसके मिनट्स हैं मेरे पास 82 बस्तियों की लिस्ट को डूसिब की वेबसाइट से बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर किसी कायदे-कानून के हटा दिया गया। प्रवीण भाई ने जिस बस्ती का जिक्र किया वो तो संभवतः 675 की लिस्ट में है फिर भी वो टूटी लेकिन उन 82 बस्तियों को क्यों हटाया गया इसके ऊपर में पिछली बैठक में जब मंत्री महोदय ने सवाल किया तो अधिकारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था ये लिखा हुआ है मैंने सारे पोर्सन अध्यक्ष महोदय हाइलाइट किये हुए हैं। ये 82वां जो उस मीटिंग का मिनट्स है उसमें लिस्टेड है। पहले अपलोड किया गया इन 82 बस्तियों की लिस्ट को इसके बाद कोई संतोषजनक उत्तर न देते हुए यह कहा गया कि जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनका कोऑपरेशन नहीं मिला, आपको कोऑपरेशन लेना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आप ऐसा नहीं कहकर पल्ला झाड़ सकते। ये कहना नितांत अपर्याप्त है कि लैंड ओनिंग एजेंसीज आई नहीं कोऑपरेट नहीं किया इसलिए हमने 82 बस्तियों के अंदर पत्थर नहीं लोग रहते हैं जीते-जागते हाड़ मांस उनके शरीर में खून बहता है हमारे जैसा दिल धड़कता है उनके सीने के अंदर। लोग रहते हैं जिंदा इंसान रहते हैं आपने एक झटके में उनको उस अनुसूची से हटाकर उनके सर से छत छीनने का रास्ता साफ कर दिया है। मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय और यही मानना दिल्ली की सरकार का है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का है कि रोटी, कपड़ा

और मकान ये प्रारब्ध और प्रयास ईश्वर की कृपा होती है तो मिलता है या आदमी के प्रयास होते हैं तो मिलता है और किसी भी सरकार की औकात नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकार का ये हक नहीं होना चाहिए कि वो रोटी, कपड़ा या मकान में से कोई भी चीज गरीब के हाथ से छीन ले। केन्द्र की सरकार वो काम करने की घिनौनी हरकत कर रही है अध्यक्ष महोदय। बहुत शर्मनाक है कि अभी तक भी उस मीटिंग में लास्ट बोर्ड मीटिंग में अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने क्लीयर इंस्ट्रक्शन दिये हैं लिखा हुआ है यहां पर 'the Hon'ble Minister, UD therefore directed that the list of 82 JJ clusters should be added and be uploaded on the website of DUSIB. It was also directed to follow up with the land owning agency to conduct the joint survey of this 82 missing JJ clusters with land owning agencies.' साफ-साफ लिखा हुआ है अभी भी उनको ऐड किया गया है या नहीं किया गया है पता नहीं, नहीं किया गया होगा। जिस तरह की मनमानी चल रही है अधिकारियों की जिस तरह का तंत्र है इस समय अस्तित्व में है नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, डूसिब का एक्ट है डूसिब एक्ट 2010 का है ये एक्ट कहता है कि नियमित रूप से जो जेजे क्लस्टर्स हैं उनके सर्वे होते रहने चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं किस तरह से जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है गरीब लोगों के सर से छत न छिने उनके निकम्मेपन का और कुछ अधिनियमों के अंदर जो लूपहोल हैं उनका फायदा उठाकर केन्द्र सरकार की एजेंसियां क्या गुल खिला

रही हैं उसका सबूत मैं आपके सामने दूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं उदाहरण के तौर पर जिक्र करना चाहूंगा जिसका जिक्र अभी अखिलेश भाई ने किया सुभाष कैंप का एनटीपीसी बदरपुर हमारे एलओपी साहब इस समय होते तो उनकी भी टिप्पणी मैं लेने की कोशिश मैं करता। डीडीए ने डिमोलिशन का आधार बनाया इस नक्शे को अध्यक्ष महोदय ये एरियल व्यू है उस जगह का रैड वाला जो एरिया है वो डीडीए ने दिखाया है कि भई इतना ही होना चाहिए इसके बियोंड नहीं होना चाहिए ये डीडीए ने लिखा है अध्यक्ष महोदय। हकीकत क्या है, हकीकत बिलकुल इसके उल्टा है अध्यक्ष महोदय। मैं आपको दिखाता हूं जो बस्ती है उसका प्रसार उसका विस्तार कितना है वो मैं आपको दिखाता हूं अध्यक्ष महोदय। ये सुभाष कैंप का 2011 का सेटेलाइट इमेज है आप देखिये जो रैड से मार्क की गई बाउंड्री है वो हैबिटेट आलरेडी लोग वहां पर रह रहे हैं ये 2011 का है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद ये 2015 का है सेम इमेज अध्यक्ष महोदय वही सुभाष कैंप है जो एलओपी साहब के इलाके में आता है जो रैड बाउंड्री दिख रही है आपको ये यहां पर आबादी है यहां पर लोग रह रहे हैं 2015 का नक्शा है और ये लेटेस्ट है अध्यक्ष महोदय 2022 का नक्शा है। 2011, 15, 22 सब में आप कुछ मत करिये गूगल मैप खोलेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि कितने एरिया में आबादी है किस जमीन के किस भूभाग पर लोग रह रहे हैं तब भी अगर आप इस नक्शे को आधार बनाते हैं और डिमोलिशन करते हैं, डीडीए अगर डिमोलिशन करती है तो इसका

मतलब कि डीडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के 30 परसेंट लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो उनको जान से मारना चाहते हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है अध्यक्ष महोदय, ये क्रिमिनल एक्ट है। अध्यक्ष महोदय, ये सर्वे नियमित रूप से होते रहने चाहिए और बड़े अफसोस की बात है कि पिछले बोर्ड मीटिंग में इसके लिए भी मंत्री महोदय ने निर्देशित किया कि भई लैंड ओनिंग एजेंसी से बात करिये, बात करके एक ज्वाइंट टीम बनाईये और ज्वाइंट टीम बनाकर प्रापर तरीके से डोर टू डोर सर्वे करना पड़े तो डोर टू डोर सर्वे करिये। 2019 में दिल्ली की सरकार ने इस काम को किया अध्यक्ष महोदय पर वो ठीक से नहीं हो पाया। उसमें और प्रयास की जरूरत है और एफर्ट्स की जरूरत है लेकिन नीयत तो हो। केन्द्र सरकार भारतीय जनता पार्टी इशारे पर या दबाव में आकर अगर ये सर्वे ठीक से नहीं किये गये अध्यक्ष महोदय तो 82 बस्तियों पर तो तलवार लटक रही है पता नहीं कितनी बस्तियां इसकी जद में आएंगी क्योंकि जो 675 हैं वहां भी कायदे-कानून का पालन होता तो जो सुंदर नर्सरी वाला हुआ वो घटना नहीं होती अध्यक्ष महोदय। तो इसका मतलब कि अब pretentious भी नहीं हो रहे कि हम कायदे-कानून का अनुपालन blatantly जो है ये क्या कर रहे हैं कानून की धज्जियां उड़ाकर बस्तियां तोड़ी जा रही हैं अध्यक्ष महोदय। थोड़ा बहुत इनक्रोचमेंट होता है उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं उसको भी एड्रेस किया जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन आप अब ये भी गारंटी नहीं है कि जो

675 अधिसूचित बस्तियां हैं वो बचेंगी कि नहीं केन्द्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार के सामने उस पर भी सवालिया निशान हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो अनुमान है मोटा-मोटा उस अनुमान के मुताबिक 675 बस्तियों के अलावा तकरीबन 1000 अभी भी क्लस्टर्स ऐसे होंगे जिनको कि सर्वे करके और डूसिब की लिस्ट में उनको इन्क्लूड करने की आवश्यकता है अगर ठीक से सर्वे किया गया तो और जो हुआ भी है सर्वे चूंकि वो ठीक से नहीं किया गया है तो उसको भी दोबारा ठीक से करवाया नहीं जाएगा तो अभी भी उन लोकेशंस पर बहुत सारे मकान छूटेंगे, उन लूपहोल्स का फायदा उठाकर डीडीए डिमोलिशंस करेगी और हजारों लोगों के सिर से फिर से छत छिन जाएगी अध्यक्ष महोदय। ये एक और तलब बात है अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली के अंदर कि लगभग 30 प्रतिशत आबादी यानी इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग दिल्ली के कुल भू-भाग में से आज भी ध्यान दीजिएगा दशमलव पांच प्रतिशत एरिया पर ही रह रहे हैं 30 परसेंट लोग। ये किस सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम किस तरह की इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, हम किस तरह के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक अधिकार की बात कर रहे हैं जहां एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 30 परसेंट लोग कुल क्षेत्र के मात्र चवपदज 5 परसेंट एरिया पर ड्वेल कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। गरीब आदमी क्या करेंगा उसके जहन में एक ही बात है किः

"रात पड़े घर जाना है सुबह तलक मर जाना है।"

सुबह क्या वही कवायद है रोटी-कपड़ा-मकान की कवायद शुरु हो जाती है, सुबह कुंआ खोदता है शाम को पानी पीता है, रात होती है सुबह क्या होगा पता नहीं और ऐसे लोगों के सर से छत छीनना बहुत सारी आहें। मैं आप समझिये अध्यक्ष महोदय पहले गुस्सा आता है जब गलत होता है तो लेकिन गुस्सा आते-आते एक स्थिति ऐसी आती है कि हताशा में तब्दील होता है वो गुस्सा, पीड़ा में तब्दील होता है गुस्सा, निराशा और कुंठा में तब्दील होता है। मैं निराश हूं, मैं हताश हूं, पीड़ित हूं और कुंठित हूं गुस्सा खत्म हो गया अध्यक्ष महोदय। डीडीए का जो रि-डवलपमेंट का मॉडल है रिहैब, रि-डवलपमेंट का मॉडल है बिलकुल असफल हो रहा है अध्यक्ष महोदय इसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। लेटेस्ट एग्जाम्पल खबरें पढ़ी मैंने खजूरी के अंदर वकील भाई के मकान को तोड़ने के बाद माननीय एलजी साहब ने उनको मकान आफर किया, मकान कहां आफर किया नरेला चले जाओ। वकील भाई रोजी-रोटी उनकी चलती है खजूरी में श्रीराम कालोनी में, वहां उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नातेदार हैं उनका अपना सामाजिक दायरा है वो सब कुछ छोड़कर नरेला जाकर क्या करने जाएंगे अध्यक्ष महोदय? ये on the very beginning this whole plan and model itself is a flawed model. आज अध्यक्ष महोदय। जब तक इसको हम इंक्ल्यूजिव नहीं करेंगे कि जहां लोग रहते हैं वहां उनका रोजगार होता है, रोजी रोटी होती है, उनका सामाजिक प्रभाव क्षेत्र होता है उनको अगर वहीं

नहीं बसायेंगे तो किसी भी तरह की बसावट की योजना, पॉलिसी असफल होगी इसका ज्ञान नहीं है अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल आईडिया नहीं है लिहाजा ऐसे लोग पॉलिसी एयर कंडीशंड कमरों में बैठ कर बना रहे हैं जिनको इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दर्द से कोई वास्ता नहीं है, कोई रासता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2019 में दिल्ली की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे भागीरथ प्रयास किये, सर्वे करवाया, स्टूडेंट्स को एंगेज किया, सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्यूट करना शुरू किये और पूरी प्लानिंग हुई। मेरे अपने विधान सभा के अंदर और तमाम विधायक साथियों के विधान सभाओं के अंदर सीएम साहब ने मीटिंग ली, एरियाज़ बताये कि भई तुम्हारे यहां की जो बस्ती है जगह ढूंढो, वहां पे हम पद situ मॉडल के तहत डेवलप करके फ्लैट्स देंगे लोगों को। वहीं पे केंद्र की सरकार ने उस पूरी योजना को कुचल के रख दिया अध्यक्ष महोदय। हमारे अपने ही फ्लैटों को अपने कब्जे में ले लिया, रेंटिंग हाउसिंग स्कीम के तहत जिसको हम दोबारा से रिएलोकेट करेंगे बोल के अध्यक्ष महोदय। तो जितने भी प्रयास दिल्ली की सरकार ने किये अध्यक्ष महोदय, उन प्रयासों को भी केंद्र की सरकार ने अपने राजनीतिक अहंकार की भट्ठी में झोंक दिया बिना इस बात की चिंता किये कि दिल्ली में अभी भी 30 प्रतिशत लोग हमारी और हम पॉलिसी मेकर्स की ओर, और हम सरकारों की ओर टकटकी लगाये इस उम्मीद से देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा लिखेंगे अपने कानूनों में, और अपने नियमों में, अपनी

नीतियों में जिससे कम से कम महल तो नहीं, पर सर एक छत मुहैया हो जायेगी। इस उम्मीद में देख रहे हैं हमारी तरफ अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कई सारे मॉडल्स हैं उड़ीसा का बहुत ंचचसंनक किया जाने वाला मॉडल है झुग्गियों के डवलपमेंट के लिये, उनके रिहैबिलिटेशन के लिये पंजाब की सरकार का मॉडल काबिले तारीफ है। यहां पे माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं सौरभ भाई बैठे हुए हैं इनसे आग्रह करूंगा उन पॉलिसिज़ को भी संज्ञान में लायें और दिल्ली के अंदर जो रहने वाले लोग हैं तकरीबन 160 लोकेशंस ऐसी हैं 160 लोकेशन के उपर या तो ड्यूसिब है, या तो एमसीडी है। सौभाग्य से हम एमसीडी में हैं। इनको विश्वास में लेके इनको थोड़ा सा सेंसिटाईज करके कुछ ऐसे निर्देश दिये जायें, कुछ ऐसी पॉलिसिज़ बनायी जायें कि दिल्ली के अंदर की 30 प्रतिशत आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, यह सोच के सोये कि कल सुबह उठेंगे तो शाम को अगली शाम को सर पे छत रहेगी कि नहीं इस चिंता के साथ, घर के बाहर में रोटी का जुगाड़ करने के लिये निकलना पड़ेगा। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय। अहमद साहब एक बहुत अच्छे शायर हैं उन्होंने लिखा है कि

''कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना
कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना
यहां पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं।''

बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय श्रीमान सौरभ भारद्वाज जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी है दिलीप भाई ने चर्चा के अंदर पुराने मीटिंग्स का जिक्र किया और बोर्ड की मीटिंग्स को किसी ने पढ़ा ये बड़ी जरूरी बात है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की दिलीप भाई ने इस मीटिंग के नोट्स को पढ़ा, उसके बारे में चर्चा की। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा काफी अर्बन विधान सभा है, ज्यादा झुग्गी झोपड़ी मेरे यहां नहीं हैं मगर जब से मेरे पास ये ड्यूसिब का विभाग आया है तब से इस विषय के उपर कई बार चर्चा विभाग के उपर हुई और मैंने देखा कि झुग्गी झोपड़ी को देखने का परस्पेक्टिव जिसके पास आधी नॉलेज है, आधा ज्ञान है उसका अलग है, जिसने पूरी प्रॉब्लम समझी है उनका अलग है। इसीलिये देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतों में जहां के judges जाहिर सी बात है झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहते हैं, जाहिर सी बात है कि वो झुग्गी झोपड़ी वालों के वोट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखा कि अगर दिल्ली शहर बसा आपने कोठियां बसा दी ग्रेटर कैलाश की, साउथ एक्स की, उन कोठियों में काम करने वाली आया, धोबी, ड्राईवर, ये सब कहां रहेंगे, कोठियों में रहेंगे, कोठियों में तो कोई व्यवस्था नहीं है। आपने इस श्रेणी के लोगों के रहने की व्यवस्था एक शहर को बसाते वक्त करी ही नहीं। इसीलिये ये गरीब लोग अलग अलग

जगह जे.जे. क्लस्टर्स के रूप में रहने लगे। कौन रहना चाहता है जे. जे. क्लस्टर्स में, कोई नहीं। जानवरों जैसे हालात होते हैं उसके अंदर। जब सरकार आई, अब ये भी कई बार लोगों के मन में ऐसा होता है कि भई पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी वालों ने ही इन जे.जे. क्लस्टर को बसाया है, नहीं ऐसा नहीं है। कानून में बहुत स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष जी जब 2015 में फरवरी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी उससे पहले तो 49 दिन की हमारी सरकार थी कट आफ डेट 2006 की है, एक जनवरी 2006 से पहले बसी हुई जे.जे. क्लस्टर्स बस्तियां और एक जनवरी 2015 से पहले आये हुए वो लोग जो इन बस्तियों में आये, तो हमारा तो कोई इससे लेना देना नहीं है, हमारी सरकार बनी फरवरी में, हमने कट आफ डेट रखी है एक जनवरी 2015, उन लोगों को प्रोटेक्शन ड्यूसिब के एक्ट में प्रोवाईड की और ये प्रोटेक्शन हमने प्रोवाईड की और प्रेजिडेंट आफ इंडिया तक जो है इसका नोटिफिकेशन हुआ है इस पॉलिसी का कि ये बस्तियां प्रोटेक्टिड हैं और अब तक इतने वर्षो तक कोई भी सरकार आई वो इसको प्रोटेक्टिड मानती थी। पिछले डेढ दो सालों में ऐसा क्या हुआ है अध्यक्ष जी कि मैं आपको एक नहीं दर्जनों जगहों के बारे में बताउं कि यहां पे दिन रात डेमोलिशन किये गये, तुगलकाबाद, मैहरोली, जामिया नगर, जाकिर नगर, यमुना पुश्ता, पंजाबी बाग, मयूर विहार, प्रगति मैदान, बेला एस्टेट, धौला कुआं, प्रियंका गांधी कैंप, जहांगीर पुरी, शांति वन, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, विजय घाट, गोविंद पुरी, कालका जी, ग्यास पुर,

सुभाष कैंप, बदरपुर, वसंत कुंज और जाने कहां कहां। लगातार पिछले डेढ दो सालों से डेमोलिशन हो रहे हैं। मैंने लिखित में कहा है कि भई डेमोलिशन किसकी अथॉरिटी से हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट। जब मैं नया नया आया तो घोसिया कालोनी है मैहरोली में, वहां के डेमोलिशन के उपर काफी चर्चा हो रही थी कि भई यहां डेमोलिशन हो रहा है। पता चला तो वो 82 कालोनियों की लिस्ट है जो ड्यूसिब ने अपनी वेबसाईट पे डाली थी कि ये कालोनियां जे.जे. क्लस्टर्स प्रोटेक्टिड हैं, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी। ड्यूसिब के वकीलों ने कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र पे कहा है कि ये 82 कालोनियां जो हैं ये हमारी वेबसाईट पे हैं, इनको भी प्रोटेक्शन है। क्या बदला पिछले साल कि अचानक ड्यूसिब के वकील ने हलफनामे में कहा कि जी ये कालोनियां कैसे आईं, हमें पता ही नहीं। अचानक वेबसाईट से इन कालोनियों को क्यूं हटा लिया गया, किसके निर्देश पे हटा लिया गया, मैंने पूछा? उस वक्त ड्यूसिब की सीईओ गरिमा गुप्ता से लिखित में पूछा ये 82 कालोनियों को कैसे हटा लिया आपने वेबसाईट से, सर पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो है इसके पीछे? और अध्यक्ष जी, जब हम कालोनियों की डेमोलिशन की बात करते हैं मोटे तौर पे मैं मीडिया के दोस्तों को बधाई दूंगा पहली बार वर्षों बाद कल मीडिया के लोगों ने जो डेमोलिशन डीडीए ने किया उसको बढ़ चढ़ के टीवी पे उठाया। पहली बार उठाया और बहुत बढ़-चढ़ के उठाया, मैं उनको धन्यवाद करूंगा उन सबको टीवी

मीडिया को भी, अखबारों को भी जिन्होंने इस बात को उठाया कि जो लोग अपनी जान की बाजी लगा कर उतराखंड में, सिलकियारा में जिन्होंने 41 मजदूरों को बचाया, उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, अपनी जान की बाजी लगा के उन्होंने उनको बचाया, उसको तब तो सब लोग हीरो कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले घर जा जाकर फोटो खींचा रहे थे, उनको कह रहे थे नेशनल हीरो हैं। आपने, डीडीए ने जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, जो एलजी साहब के डायरेक्ट आधीन आती है उसने उस आदमी के घर को बुलडोज़र से ढहा दिया। ये डीडीए की सच्चाई है। अब क्यूंकि ये मामला अखबार में आ गया, मीडिया में आ गया तो एक वकील हसन को तो एलजी साहब ने कह दिया मैं तुम्हें मकान दे दूंगा, बाकियों का क्या हो गया अध्यक्ष जी? तुगलकााद के अंदर आपने ढाई लाख लोगों को बेघर कर दिया। केंद्र सरकार की आर्किआलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने ढाई लाख लोगों को बेघर कर दिया। अध्यक्ष जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से इस हाउस से जानना चाहूंगा वो परिवार हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जवान बच्चे हैं, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे उनके जाते हैं, जवान बेटियां हैं। आप अध्यक्ष जी ये कल्पना कीजिये बरसात थी उस दिन जब ये तुगलकाबाद के अंदर डेमोलिशन किया बारिश हो रही थी, ठंड थी, बारिश का मौसम था जब सुंदर नर्सरी के पास डेमोलिशन हुआ तो ठंड भी थी। इसके अंदर डेमोलिशन कर दिया गया अध्यक्ष जी आप कल्पना कीजिये लाखों लोगों के सर के उपर से आपने छत के उपर

बुलडोज़र फेर दिया, बरसात हो रही है आपका घर का सामान तहस नहस पड़ा हुआ है, आप कहां जाओगे, कहां ले जाओगे, कहां ले जाओगे अपने बच्चों को, इस शहर में कहां ले जाओगे, सोचिये। छोटी छोटी बात के लिये इतना हल्ला होता है इस देश के अंदर, आपने ढाई लाख लोगों को बेघर कर दिया और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अभी सुंदर नर्सरी के बारे में इन्होंने बताया प्रवीन भाई ने, भरी ठंडमें अध्यक्ष जी, ठंड के अंदर हमारे ड्यूसिब के वकील ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हमारे ड्यूसिब के वकील ने, सरकारी वकील ने, जिनका नाम परमिन्दर चौहान है, मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये विधान सभा के रिकार्ड में आये, कभी अगर कानून का पहिया चलेगा, कभी कानून के हाथ इन वकीलों की गर्दन तक पहुंचेंगे तो इस रिकार्ड में रहेगा ड्यूसिब के स्टैंडिंग काउंसिल परमिन्दर चौहान ने हाईकोर्ट के अंदर झूठा हलफनामा दिया, पर्जरी की उन्होंने, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि ये जो प्रवीन कुमार जी के यहां सुंदर नगरी वाली जो बस्ती है वो 675 की लिस्ट में नहीं है जबकि अध्यक्ष जी वो लिस्ट में थी, मैंने फाईल देखी है। आज भी वो वेबसाईट पे उसका नाम डला हुआ है, फाईल पे ड्यूसिब ने लिखा है एफिडेविट के लिये कि ये बस्ती 675 बस्तियों की लिस्ट में है और उसी फाईल पे परमिन्दर चौहान ने जो एफिडेविट बनाया उसके अंदर उसने वो लाईन गायब कर दी। उसको बेस बना के हाईकोर्ट ने 2019 में आर्डर कर दिये कि ये बस्ती इल्लिगल है, इसको डेमोलिशन कर दीजिये। 2019 में उसके उपर

कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस्ती के गरीब लोगों ने कहा कि चलो मामला टल गया। अभी पिछले 2 महीने, 3 महीने पहले 2023 में कुछ लोग जो हाईकोर्ट में चले गये कि कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट में फिर से वो परमिन्दर चौहान जो है ड्यूसिब की तरफ से पेश हो गये। मैंने अपने हाथ से लिखा कि नहीं परमिन्दर चौहान पेश नहीं होंगे, वो कैसे पेश हो सकते हैं, हमने अपनी तरफ से संतोष त्रिपाठी को खड़ा किया। संतोष त्रिपाठी मेरी तरफ से खड़े हुए हाईकोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा मिलार्ड ये झूठा बयान यहां पे दिया गया है, ये गलत आर्डर हो गया है। कोर्ट ने कहा अब तो कंटेम्प्ट में आये हैं आप लोग, मैं तो पुराने जज साहब ने जो आर्डर दे दिया मैं तो सिर्फ उस आर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिये बैठा हूं, मैं मेरिट में नहीं जा सकता। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसको तो करना पड़ेगा मगर देखिये उन जज साहब के दिल में थोड़ी सी मानवता थी, हमारे वकील ने कहा साहब पॉल्यूशन है, ग्रैब की बंदिशें हैं कम से कम जब तक ग्रैब लागू है तब तक की मोहलत दे दो, हमारे वकील ने ये सोचा ग्रैब की मोहलत मिल जायेगी इतनी देर में हम सुप्रीम कोर्ट चले जायेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम ये बात रखेंगे कि हमारा वकील झूठा है, हमारे वकील ने हलफनामे पे झूठ बोला, पर्जरी की, सुप्रीम कोर्ट के तो दिल में दया आयेगी, हजारों बच्चों का सवाल है। हमारे आदमी ने कहा कि चलिये संतोष त्रिपाठी जी ने ग्रैब के नाम पे मोहलत मांगी, कोर्ट का दिल पसीजा, कोर्ट ने कहा ठीक है ग्रैब की मोहलत है। अब आप देखिये कि बेशर्मी

देखिये केंद्र सरकार की, और मुझे लगता है कि बद्दुआ लगेगी उन सब लोगों की, उनके बच्चों की, इनकी बेशर्मी देखिये ग्रैब के अंदर सीएक्यूएम ने स्पेशल परमिशन दी, आज तक दी है इन्होंने किसी को परमिशन, इन्होंने एक झुग्गी बस्ती को उजाड़ने के लिये ग्रैब के सीएक्यूएएम ने स्पेशल परमिशन दी कि ग्रैब लागू है तो है, इस बस्ती को डेमोलिश कर दो और उसको रात मतलब दो घंटे के अंदर उन्होंने पूरी बस्ती तहस नहस कर दी, ये बेशर्मी है। और अध्यक्ष जी कोई पत्ता नहीं हिल रहा इस शहर के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूं, मैंने लिखित में दिया, ये क्वेश्चन लगा था विधान सभा के अंदर हमारी बहन भावना गौड़ ने लगाया था कि क्या ये सच है ड्यूसिब के वकील ने अदालत में झूठ बोला। तो ये जवाब मेरे पास जब आया क्योंकि मैं इस प्रोसेस के अंदर रहा हूं इस विधान सभा के अंदर, मंत्री के तौर पर मेरे पास इसका जवाब आया, तो इसका जवाब गोलमोल आया कि न हां में, न न में। मैंने कहा ये काम नहीं चलेगा मुझे जो है असेम्बली के अंदर जवाब देना है और फैक्चुअल जवाब देना है। इसको सही करके ले के आओ और आपके नाम का मैंने उनको थोड़ा डर दिखाया असेम्बली का, मैंने कहा देख लो असेम्बली के अंदर प्रिविलिज हो जायेगी। तो जब इस असेम्बली के मेरे से नहीं डरते, असेम्बली से डरते हैं, तो इस असेम्बली के डर में फिर जो है ये मामला वापिस गया डिपार्टमेंट में, फिर उन्होंने लिखित में

दिया कि हां ये बात सच है ये बस्ती लिस्टिड क्लस्टर थी। ड्यूसिब ने कहा था लिस्टिड क्लस्टर है, वकील ने एफिडेविट में झूठ बोला। तो फिर मैंने दोबारा उस फाईल पे लिखा मैंने कहा जब वकील ने झूठ बोला तो तुमने उसके उपर क्या कार्रवाई की, कार्रवाई बताओ? फिर फाईल गयी। अगले दिन सुबह 11 बजे यहां पे आये तो बोला कि साहब हमने वकील को शो कॉज नोटिस दे दिया है। अब शो कॉज नोटिस के बाद क्या किया उन्होंने मुझे नहीं मालूम। मैं ये लिख के दे चुका हूं ड्यूसिब को कि जो वकील ऑन रिकार्ड झूठ बोल चुका है और हजारों लोगों को बेघर कर चुका है इस वकील को हटाओ। उस वकील को नहीं हटाया जा रहा। पता नहीं इनका चाचा लगता, ताउ लगता, क्या लगता है वो। क्यों नहीं हटाया जा रहा अध्यक्ष जी इस बात को समझिये क्योंकि पूरा षडयंत्र जो है वो ये है कि किसी तरीके से इस शहर से जितने भी गरीब लोग हैं उनको जो है बर्बाद करके भगा दिया जाये। ये ष्टाडयंत्र चल रहा है इस शहर में, जिस शहर में जहां पे लोग जो है एम्स के सामने ब्रेड बांट के अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, इस शहर में जहां पे रामनवमी के दिन लोग भंडारा करके अपने आपको धर्मात्मा समझते हैं, उस शहर में आज गरीब लोगों को इस तरीके से बेघर करके बर्बाद किया जा रहा है और एक दो नहीं, लाखों लोगों को पिछले डेढ साल के अंदर इस तरीके से अध्यक्ष जी बर्बाद किया गया है। मैं और भी कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यमुना पुश्ते पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हैं नहीं,

ये एक एक नाईट शेल्टर के लिये रोना रोते हैं कि इस नाईट शेल्टर के अंदर ये खराब हो गया, इस नाईट शेल्टर के अंदर ऐसा हो गया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यमुना पुश्ते पे नाईट शेल्टर बना रखे थे अध्यक्ष जी। पिछले साल इन्होंने वो नाईट शेल्टर तोड़ दिये। ये खबर मेरे तक आई, मैंने सीईओ से लिखित में पूछा कि ये नाईट शेल्टर कैसे तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला और एलजी सुनते हैं तो सुन लें, उन्होंने मुझे बोला अध्यक्ष जी पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं इस हाउस के सामने, उन्होंने बोला कि एलजी साहब की डायरेक्शन है इसलिये नाईट शेल्टर तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनको लिखित में कहा आप मुझे लिखित में आर्डर दीजिये किसके आर्डरपे ये नाईट शेल्टर तोड़े जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया, वो खत मेरे पास है, सारी मेरे पास रिटन जो हैं मैंने जो इनसे वो करी है कोरसपोंडेंस सारी हैं। मैंने कहा कि अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि उनको हायर अथॉरिटीज की डायरेक्शन हैं। ये हायर अथॉरिटीज कौन हैं, न मैं हूं न मुख्यमंत्री हैं, किसकी डायरेक्शन पे, कोई जवाब नहीं आया। वो नाईट शेल्टर के लिये कोई एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में गयी, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुई, 8 शेल्टर टूट चुके थे, 5 बच गये थे, इसलिये 5 रूक गये 8 डेस्ट्राय कर दिये। और जो 5 बच गये अध्यक्ष जी, इनको भी इस साल सर्दियों की शुरूआत में 2023 की शुरूआत में नवम्बर या दिसम्बर में इनको भी लॉक कर दिया गया। और जब ये मेरे पास खबर आई तो मैंने दोबारा पूछा भई

इनको किसके कहने पे आपने लॉक कर दिया, अखबार के अंदर छपा है तो उनको खोल तो दिया गया मगर ये नहीं बताया गया कि ये किसके कहने पे किया जा रहा है। मैंने तब प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि पहले भी जो नाईट शेल्टर डेमोलिश हुए हैं वो एलजी साहब के डायरेक्शंस पे हुए हैं तो एलजी साहब बड़े नाराज हुए, उन्होंने प्रेस रिलीज दिया कि जो मंत्री हैं झूठ बोल रहा है। भैया मैं झूठ बोल रहा हूं मैं मान लेता हूं चलो, एलजी साहब सुनते हैं मेरा भाषण मुझे पता है इसलिये मैं उनके लिये बता रहा हूं ये बात, सौरभ भारद्वाज झूठा है, जिस सीईओ ने वो नाईट शेल्टर डेस्ट्राय किये आप उसको क्यूं नहीं सस्पेंड कर रहे। मैं तो लिखित में दे चुका हूं, आप करो उसको सस्पेंड। गरिमा गुप्ता उस वक्त सीईओ ड्यूसिब होती थी, उन्होंने उस वक्त नाईट शेल्टर डेस्ट्राय किये, सौरभ भारद्वाज कह रहा है कि गरिमा गुप्ता ने कहा कि एलजी साहब ने कहे थे इसलिये डेमोलिश हुए, मैंने कहा नहीं, मैंने लिखित में कहा कि इनको डेस्ट्राय नहीं करना था, तो अगर उस अफसर ने किसी के बिना डायरेक्शन के नाईट शेल्टर डेस्ट्राय कर दिये तो एलजी साहब उसको क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे मुझे बतायें, क्यों नहीं उसके उपर कार्रवाई हो रही? भई या तो वो मेरी बात मान रही है या वो एलजी साहब की बात मान रही है। मैं लिखित में कह रहा हूं कि वो मेरी बात नहीं मान रही, इसका मतलब एलजी साहब की बात मान रही है न, उनका संरक्षण है न? साफ साफ बात है। तो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर अध्यक्ष जी

मौखिक आदेश दे के जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनको दुखी किया जा रहा है और पता नहीं कितने लोग मर गये होंगे। बहुत लोग मर गये होंगे अध्यक्ष जी। आप सोचो लाखों लोगों को आप बेघर कर रहे हो, किसी के घर कोई बुजुर्ग है, किसी के घर कोई बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा उनका। मगर कोई सोचने वाला ही नहीं है देश के अंदर, कोई समझने वाला ही नहीं है, मैं हैरान हूं ऐसे अफसरों को, अरे इस्तीफा दे दो, आप कैसे ऐसे इल्लिगल और आप पूरी इंसानियत के खिलाफ आप ऐसे काम कर कैसे सकते हैं, और अफसर कर रहे हैं, भई ऐसा क्या डर है तुम्हें, फांसी दे देगा एलजी, क्या हो जायेगा। आप गरीब लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, आप जो बेचारे मरीज हैं, उनको आप दवाई नहीं देने दे रहे, लोगों के आपने टैस्ट बंद कर दिये, अस्पतालों में आपने आपरेशन बंद कर दिये, आप क्या करके मानोगे। मतलब हद हो रखी है अध्यक्ष जी, कोई कहने वाला ही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मेरे इस भाषण से कुछ नहीं होगा मगर कभी न कभी तो ये भाषण जो आपके यहां डाक्यूमेंट होंगे कभी तो कोई इन्हें पढ़ेगा, कभी तो ताकत जनता के हाथ में वापिस आयेगी और इन अफसरों ने जिन्होंने भी एलजी की डायरेक्शन पे ये सारे काले कारनामे किये हैं इनको सजा मिलेगी इसलिये मैं ये बातें कह रहा हूं ताकि ये सारी की सारी चीज रिकार्ड पे रहे कि ये सब यहां पे हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः गंभीर चर्चा हुई है तैयारी से दिलीप पांडे जी ने भी और माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय को रखा है, इस पर एक बार मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी हों, दोबारा सौरभ जी कुछ प्लानिंग करें, अधिकारियों को यहां बुलाया जाये एक एक अधिकारी को, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिये। आज जैसा माननीय मंत्री महोदया आतिशी जी ने कहा है कि सोमवार को बजट रखा जायेगा इसलिये बजट से संबंधित सरकारी कामकाज लंबित हैं। सदन अगर सहमत है तो सत्र की अवधि दिनांक 08 मार्च 2024 तक बढ़ाई जा सकती है, अगर

सदन इस पर सहमत है तो हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

माननीय सदस्यः 8 मार्च।

माननीय अध्यक्षः हां मार्च।

माननीय सदस्यः आठ मार्च।

माननीय अध्यक्षः आठ मार्च ही बोला है। नहीं आठ मार्च बोला है। आठ मार्च।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः ऐसा लगा मार्च की जगह पांच बोला है।

माननीय अध्यक्षः नहीं आठ मार्च ही लिखा हुआ है, आठ मार्च ही बोला है हो सकता है गलती हो गयी हो आठ मार्च 2024 तक बढ़ाई जाये।

जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

मुझे लगता है सदन सहमत है अतः दिनांक 08 मार्च 2024 तक सदन की बैठकें आयोजित होंगी। अब सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 04 मार्च, 2024 को पूर्वाहन् ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। आप सभी लंच के लिये सादर आमंत्रित हैं।

(सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 04 मार्च, 2024 को पूर्वाहन् ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।